जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक: 118 दिनांक:01-09-2024 रविवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने तीसरे कार्यकाल के बड़े फैसलों का जिक्र ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में किया। पीएम ने कहा कि 100 दिन के अंदर 11 लाख नई लखपति दीदी बनी हैं। इसी समय अवधि में दो लाख करोड़ रुपये के पीएम पैकेज की घोषणा की गई।

जाति जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर एक जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि जातिवार जनगणना कराने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए जाएं।

हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदली

1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोटिंग

नई दिल्ली (ईएमएस)।भारतीय निर्वाचन आयोग ने हरियाणा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। आयोग ने हरियाणा के लिए मतदान के दिन को 1 अक्तूबर से संशोधित करते हुए 5 अक्टूबर, 2024 कर दिया है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना का दिन 4 अक्तूबर से बदलकर 8 अक्तूबर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मतदान की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव करने का अनुरोध आयोग से किया था। इसके बाद आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है।

निर्वाचन आयोग ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय बिश्नोई समुदाय के मतदान अधिकारों और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए लिया गया है। आयोग ने कहा कि बिश्नोई समुदाय ने गुरु जम्भेश्वर की याद में आसोज अमावस्या उत्सव में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को बरकरार रखा है।

राज्य भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने भारत निर्वाचन आयोग और हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिख मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। आयोग को लिखे पत्र में भाजपा ने दलील दी थी कि 28 व 29 सितंबर को शनिवार व रविवार है। एक अक्तूबर को मतदान होने की वजह से छुट्टी है। दो अक्तूबर को गांधी जयंती और तीन को अग्रसेन जयंती है। 30 की छुट्टी लेकर छह दिन का लंबा वीकेंड पड़ रहा है। ऐसे में लोग छुट्टियां मनाने प्रदेश के बाहर जा सकते हैं जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है।

भाजपा ने अपने पत्र में यह भी तर्क दिया था कि दो अक्तूबर को आसोज की अमावस्या होने के कारण बीकानेर के मुकाम गांव में बिश्नोई समाज का धार्मिक अनुष्ठान है। इसके लिए बिश्नोई समाज के काफी लोग एक अक्तूबर को ही पहुंच जाते हैं। इसका भी मतदान प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। भाजपा ने आयोग से यह भी कहा था कि अगली तारीख रखते हुए यह ध्यान रखा जाए कि मतदान की तिथि से एक दिन पहले और मतदान के अगले दिन अवकाश न हो। ऐसा होने से ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा ले सकेंगे।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बीते हफ्ते चुनाव की तारीख की घोषणा की थी। पूर्व कार्यक्रम के मुताबिक पांच सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होनी है। वहीं एक अक्तूबर को मतदान और चार को परिणाम घोषित किए जाने थे, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। चुनाव आयोग इससे पहले भी तारीख में बदलाव कर चुका है। साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख 14 फरवरी निर्धारित की गई थी। इसके दो दिन बाद रविदास जयंती थी। पंजाब के काफी लोग रविदास जयंती मनाने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाते हैं। पंजाब के राजनीतिक दलों के अनुरोध के बाद चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख में परिवर्तन कर दिया था।

इस बार लोकसभा चुनाव में गर्मी की वजह से मतदान प्रतिशत में करीब पांच फीसदी की गिरावट आई थी। 25 मई को भीषण गर्मी थी और लोग घरों से मतदान के लिए नहीं निकले। 2019 में करीब 70 फीसदी मतदान हुआ था। जबकि बीते मई को 65 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था।

आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत

विजयवाड़ा (ईएमएस)। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के चलते मुगलराजपुरम इलाके में हुए लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है विजयवाड़ा के मोगलराजपुरम इलाके में भूस्खलन के कारण बड़े-बड़े पत्थर मृतकों के घरों पर गिर गए।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भूस्खलन पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की राशि देने का एलान किया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, विजयवाड़ा के मोगलराजपुरम में भूस्खलन हुआ, जिससे चार लोगों की मौत हो गई। सीएम नायडू ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है उन्होंने प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिजनों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का एलान किया।

सीएम ने अधिकारियों को भूस्खलन की आशंका वाले स्थानों से लोगों को दूर ट्रांसफर करने का निर्देश दिया क्योंकि अगले दो से तीन दिनों में भारी बारिश का अनुमान है।

बता दें कि गुंटूर जिले के पेदाकाकानी गांव में, हैचबैक में घर लौट रहे एक शिक्षक और दो छात्रों की एक उफनती धारा को पार करते समय उनकी कार बह जाने से मौत हो गई।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी

- एनसीआरबी के आंकड़े बेहद चौंकाने वाला

मुंबई, (ईएमएस)। क्या महिलाओं के ख़िलाफ़ अत्याचार को कोई रोक नहीं सकता? ऐसा सवाल उठने लगा है. दरअसल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के जो आंकड़े जारी किए हैं वो आँकड़ा बेहद चौंकाने वाला है. कोविड काल में जब देश भर में लॉकडाउन था तब भी महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम होने की बजाय बढ़ गई. एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी की सत्ता के दौरान, कोविड लॉकडाउन के दौरान, महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की औसतन 109 घटनाएं प्रतिदिन दर्ज की गईं। आंकड़ों से पता चलता है कि आज भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में कमी नहीं आई है। 2020 में लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की 31,701 घटनाएं हुईं। हर दिन 88 महिलाएं शिकार हुईं. हालांकि, 2021 में यह संख्या 39,266 तक पहुंच गई. यानी हर दिन महिलाओं से रेप के 109 मामले सामने आए। वहीं जनवरी से जून 2022 तक हर दिन महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की 126 घटनाएं दर्ज की गईं। जबकि जुलाई से दिसंबर 2022 तक यह संख्या थोड़ी कम होकर 116 रह गई. हालाँकि, 2023 में, औसत वापस 126 हो गया, जिससे राज्य की महिला सुरक्षा की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पॉक्सो के तहत अपराधों में वृद्धि, विशेषकर नाबालिग लड़कियों के खिलाफ छेड़छाड़ और बलात्कार के अपराध (पॉक्सो की धारा 12) में भारी वृद्धि देखी गई है।

2021 में ये अपराध 249 और 2022 में 332 तक पहुंच गए हैं. वहीं बात करें मुंबई के आंकड़ों की तो यहां के आंकड़े चिंताजनक हैं. 2023 में मुंबई में पॉक्सो के तहत बलात्कार के मामलों में मामूली गिरावट आई है। 2020 में रेप के 445 मामले सामने आए, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 524 हो गया. लेकिन 2023 में यह संख्या थोड़ी कम होकर 590 रह गई है. अपराध के बढ़ते आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है.

जम्मू और कश्मीर में भाजपा ने अनुच्छेद 370 के समर्थक को टिकट दिया, पार्टी में असंतोष

श्रीनगर (ईएमएस)। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुरजीत सिंह सलाथिया को टिकट दिए जाने का विरोध जमकर हो रहा है। शनिवार को दो और भाजपा नेताओं ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। भाजपा के सांबा जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कश्मीर सिंह फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली

पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए कश्मीर सिंह ने कहा, भारी मन से मैं उस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं जिसके लिए मैंने 42 साल तक काम किया है। मैं परिस्थितियों के कारण मजबूर था क्योंकि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) से आया था और दशकों तक हमारी विचारधारा का मुखर विरोध करता रहा।

उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कांग्रेस-एनसी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे सलाथिया 2021 में भाजपा में शामिल हुए थे। कश्मीर सिंह ने कहा - हमने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए प्रदर्शन किए और हड़तालें कीं और टिकट उस व्यक्ति को दिया गया जो हमेशा हमारी विचारधारा और अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ था। यह आम कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं है।

जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना को भेजे अपने त्यागपत्र में कश्मीर सिंह ने कहा कि अगर पार्टी सलाथिया की जगह किसी वरिष्ठ भाजपा सदस्य को लाती है तो वह अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा, अन्यथा, मैं इस संघर्ष को आगे बढ़ाऊंगा और उनके खिलाफ एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करूंगा।

चंद्र मोहन शर्मा का इस्तीफा इसके अलावा, वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता चंद्र मोहन शर्मा ने शुक्रवार को भाजपा से इस्तीफा देने की घोषणा की और धमकी दी कि अगर पार्टी आलाकमान ने सीट से किसी अन्य भाजपा नेता को मैदान में उतारने के अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो वह जम्मू पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

मीडिया से बात करते हुए 70 वर्षीय शर्मा ने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के ''अनुचित'' चयन को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने कहा, ''वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सब से दुखी हैं। मैं, भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हूं। मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।''

मॉलीवुड के 17 प्रमुख अभिनेता और कई निर्माताओं पर गंभीर आरोप

जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट से हो रहे खुलासों से विवादों में घिरी फिल्म इंडस्ट्री

बेंगलुरु,(ईएमएस)। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, जिसे मॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बड़े विवादों में घिरी हुई है। इस रिपोर्ट ने इंडस्ट्री के भीतर यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मामलों का पर्दाफाश किया है, जिससे 17 प्रमुख अभिनेता और फिल्म निर्माता आरोपों के घेरे में आ गए हैं। इन आरोपियों में इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित नाम जैसे सिद्दीकी, रंजीत बालकृष्ण, एम. मुकेश, और जयसूर्या शामिल हैं। इनमें से एम. मुकेश न केवल एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, बल्कि केरल की सत्तारूढ़ माकपा के विधायक भी हैं।

रिपोर्ट के आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे मलयालम इंडस्ट्री का मीटू आंदोलन कहा जा रहा है, जिससे पूरे फिल्म उद्योग में हलचल मच गई है। कई कलाकारों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है, जबकि जयराम, पृथ्वीराज, सुकुमारन, और उर्वशी जैसे कलाकारों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। माकपा नेता वृंदा करात ने भी अपनी ही पार्टी के विधायक मुकेश के खिलाफ कार्रवाई न करने पर केरल सरकार के प्रति नाराजगी जताई है।

रिपोर्ट में इंडस्ट्री के भीतर कास्टिंग काउच और रसूख के दुरुपयोग के कई मामले उजागर हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप, अम्मा (एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स) के अध्यक्ष मोहनलाल और अन्य पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, और संस्था को भंग कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के बाद अब तक 17 महिलाओं ने औपचारिक रूप से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करवाई है।

इस मामले में कुछ प्रमुख विधायकों के भी नाम सामने आए हैं। एक बंगाली अभिनेत्री ने फिल्म निर्माता और केरल चलचित्र अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रंजीत पर 2009 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके बाद रंजीत ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा, एक मलयालम अभिनेत्री के आरोपों के बाद अभिनेता सिद्धीकी ने भी अम्मा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। माकपा विधायक और अभिनेता एम. मुकेश, अभिनेता और निर्माता मनियानपिल्ला राजू, और अन्य के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगे हैं।

इस मामले के बढ़ते विवाद के बीच राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है ताकि रिपोर्ट में किए गए आरोपों की जांच की जा सके। हालांकि, सरकार पर कुछ आरोपियों को बचाने के आरोप लगे हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने निराधार बताया है।

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता ममूटी और मोहनलाल की चुप्पी ने भी मामले को और रहस्यमय बना दिया है। कुछ युवा अभिनेताओं ने इंडस्ट्री में सुधार की मांग की है, जबकि अभिनेत्री पार्वती ने अम्मा के पदाधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे की निंदा की है। इस पूरे मामले ने मलयालम सिनेमा को एक कठिन दौर में ला खड़ा किया है, जहां इंडस्ट्री की साख और भविष्य दोनों पर सवाल उठ रहे हैं।

चिराग पासवान की बीटेक डिग्री पर उठे सवाल

झांसी (ईएमएस)। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान की डिग्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बृजेंद्र शुक्ला ने दावा किया, चिराग के पास बीटेक डिग्री की डिग्री नहीं है। उन्होंने यहां एडमिशन तो लिया, लेकिन सिर्फ पहले सेमेस्टर की परीक्षा ही दी थी। बृजेंद्र शुक्ला बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा- चिराग पासवान ने साल 2005 में यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था।

हिज्ब-उत-तहरीर मामले में एनआईए की कार्रवाई......मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु (ईएमएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने तमिलनाडु हिज्ब-उत-तहरीर मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और इस्लामी खिलाफत स्थापित करने का प्रयास शामिल था। आरोपी को विदेश भागने की कोशिश के दौरान बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था। आरोपी की पहचान अजीज अहमद उर्फ अजीज अहमद उर्फ जलील अजीज अहमद के रूप में हुई। एनआईए ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जो कथित तौर पर चरमपंथी, कट्टरपंथी और मौलिक संगठन से प्रभावित थे जो इस्लामी खिलाफत स्थापित करने और इसके संस्थापक तकी अल-दीन अल-नभानी द्वारा लिखित संविधान को लागू करने की कोशिश कर रहे थे।

एनआईए के अनुसार, आरोपियों ने बैठकें आयोजित की थीं, जहां कई प्रतिभागियों, विशेष रूप से भोले-भाले युवाओं को हिज्ब-उत-तहरीर की विचारधारा के साथ कट्टरपंथी बनाया गया था, जो शत्रुतापूर्ण ताकतों से सैन्य सहायता (नुसरा) चाहता है। भारत को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अजीज को गुप्त बयान के संचालन में मुख्य आरंभकर्ताओं में से एक पाया गया। एनआईए द्वारा चुनाव और लोकतंत्र के खिलाफ प्रचार जैसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए एचयूटी के छह सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करने के दो महीने बाद आया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं, लगभग पचास वर्ष का एक व्यक्ति, उसके दो बेटे और तीन अन्य जिनकी उम्र 26 से 33 वर्ष के बीच थी।

आरोपियों में से एक हमीद हुसैन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और वह कॉलेजों में इंजीनियरिंग पढ़ाता था। वह अपनी विचारधारा की वकालत करते हुए यूटयूब पर वीडियो पोस्ट करने में शामिल थे, जबकि उनके पिता मंसूर इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए निजी बैठकें करते थे।

राज्यों को करों में हिस्सेदारी के रूप में 3.66 लाख करोड़ जारी, पिछले वर्ष से 57109 करोड़ ज्यादा

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार को विभिन्न कर और गैर-कर राजस्व के माध्यम से जुलाई 2024 के अंत तक कुल 10,23,406 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, प्राप्त राशि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान (बीई) का 31.9 प्रतिशत है। दूसरी ओर, करों में हिस्सेदारी के हस्तांतरण के रूप में केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को 3,66,630 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

सरकार की प्राप्तियों में कर राजस्व (केंद्र को शुद्ध) 7,15,224 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व 3,01,796 करोड़ रुपये और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां 6,386 करोड़ रुपये हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जुलाई 2024 तक के मासिक खातों को समेकित और प्रकाशित किया, जो चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। मंत्रालय की रिपोर्ट में, यह बताया गया है कि एकत्र किए गए कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।

विशेष रूप से, करों में राज्य सरकारों के हिस्से के रूप में 3,66,630 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह 57,109 करोड़ रुपये की वृद्धि है। यह सरकार द्वारा राजकोषीय संघवाद को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 3,66,630 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 57,109 करोड़ रुपये अधिक है।

व्यय पक्ष पर, सरकार ने जुलाई 2024 तक कुल 13,00,351 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो वर्ष के बजट अनुमानों का 27 प्रतिशत है। इसमें से 10,39,091 करोड़ रुपये राजस्व खाते पर खर्च किए गए हैं, जबकि 2,61,260 करोड़ रुपये पूंजी खाता व्यय के लिए निर्देशित किए गए हैं।

किसानों के बीच विनेश फोगाट....अपने हक की आवाज उठाना हमेशा राजनीति नहीं

गुरुग्राम (ईएमएस)। शंभू बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को शनिवार को 200 दिन पूरे हुए हैं। इस बीच ओलंपियन रेसलर, महिला पहलवान विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पहुंची। यहां किसानों ने विनेश का माला पहनाकर स्वागत कर सम्मान किया।

इस मौके पर विनेश ने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर कहा, किसान अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से यहां बैठे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अभी भी कम नहीं हुई है। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुई। आपकी बेटी आपके साथ है। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आपकी मांगे पूरी हों, और जब तक आप अपने अधिकार नहीं ले लेते, तब तक वापस न लौटें। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना हैं, हर बार राजनीतिक नहीं होता।

विनेश ने किसानों के समर्थन में मोदी सरकार से अपील कर कहा, किसान अपने अधिकारों के लिए 200 दिनों से बैठे हुए हैं। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए।

वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि यह शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन बहुत तीव्रता के साथ चल रहा है। उन्होंने कहा, केंद्र हमारे संकल्प की परीक्षा ले रही है और हमारी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं। किसान नेता पंधेर ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के 200 दिन पूरे होना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो किसानों के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसान बीते पांच महीने बैठे हुए हैं। अभी हाल ही में 22 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ बैठक जारी रखने का निर्देश दिया था। वहीं पंजाब और हरियाणा सरकारों ने किसानों के साथ हुई मीटिंग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। यह बैठक सुनवाई से एक दिन पहले पटियाला में हुई थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 सितंबर को होने वाली है।

400 किसान अब भी शंभू बॉर्डर पर

खबर के मुताबिक, पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से करीब 400 किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हालांकि चावल की रोपाई के बाद अधिकांश किसान अपने खेतों में वापस लौट गए हैं। शंभू बॉर्डर पर 5 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। किसान यूनियनों ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वे अपना मार्च कब फिर से शुरू करेगी।

जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ कहना बंद करे : सीजेआई

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका को ''न्यायपालिका की रीढ़'' बताकर कहा कि यह कानून का अहम घटक है। यहां 'जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन' को संबोधित कर सीजेआई ने कहा कि यह जरूरी है कि जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ कहना बंद करें। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ''न्याय की तलाश कर रहा कोई नागरिक सबसे पहले जिला न्यायपालिका से संपर्क करता है। जिला न्यायपालिका कानून का अहम घटक है।

सीजेआई ने कहा, ''इसलिए जिला न्यायपालिका से बड़ी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया जाता है और इस न्यायपालिका की रीढ़' के रूप में वर्णित किया गया है। रीढ़ तंत्रिका तंत्र का अहम अंग है। उन्होंने कहा, कानूनी व्यवस्था की रीढ़ को बनाए रखने के लिए हमें जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ न्यायपालिका कहना बंद करें। आजादी के 75 साल बाद, अब समय आया है कि हम ब्रिटिश काल के एक और अवशेष-अधीनता की औपनिवेशिक मानसिकता को दफना दें।'' न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि 2023-24 में अदालती रिकॉर्ड के 46.48 करोड़ पृष्ठों को डिजिटल रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट परियोजना के तहत 3,500 से अधिक अदालत परिसरों और 22,000 से अधिक अदालत कक्षों का कम्प्यूटरीकरण भी किया गया। देश में जिला अदालतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 2.3 करोड़ मुकदमों पर सुनवाई की।''

सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों को संविधान में मान्यता प्राप्त प्रत्येक भाषा में अनुवादित किया जा रहा है और 73,000 से अधिक अनुवादित फैसले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। न्यायपालिका की बदलती जनसांख्यिकी पर आंकड़ों का हवाला देकर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिला न्यायपालिका में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा, 2023 में राजस्थान में दीवानी न्यायाधीशों की कुल भर्ती में 58 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं। दिल्ली में 2023 में नियुक्त हुए न्यायिक अधिकारियों में 66 प्रतिशत महिलाएं थीं। उत्तर प्रदेश में 2022 में दीवानी न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के लिए नियुक्त होने वाली 54 प्रतिशत महिलाएं थीं।''

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि केरल में कुल न्यायिक अधिकारियों में से 72 प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्होंने कहा, ''ये कुछ उदाहरण हैं जो भविष्य की एक आशाजनक न्यायपालिका की तस्वीर पेश करते हैं। सीजेआई के अलावा प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी, उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी बयान के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सितंबर को समापन भाषण देंगी और उच्चतम न्यायालय के झंडे व प्रतीक चिह्न का भी अनावरण करेंगी।

यूपीएस बनाम ओपीएसः केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का जताया विरोध

अब होगी पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई

- विपक्ष को साथ लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे कर्मचारी

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की बजाए एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने की घोषणा की है। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल बजा दिया है। केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का विरोध जताया है। ये कर्मचारी संगठन, अब विपक्ष को साथ लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार, बहुत जल्द दबाव में आ जाएगी। देश में पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर कहा है कि पूरे देश के कर्मचारी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान, पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ओपीएस के लिए दोबारा से आंदोलन शुरु हो गया है।

एक करोड़ ज्यादा परेशान

प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा गया है कि देश के एक करोड़ से ज्यादा शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी, बाजार आधारित और विसंगतिपूर्ण एनपीएस व्यवस्था के दुष्परिणाम का दंश झेल रहे हैं। वे सेवानिवृत्ति के बाद इस व्यवस्था में अपने जीवन के गुजर बसर के लिए परेशान हैं। वजह, एनपीएस में जो पेंशन दी जा रही थी, वह पर्याप्त नहीं थी। पूरे देश के कर्मचारी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान, पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल न कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लाने की घोषणा कर दी गई। इसमें जो प्रावधान हैं, उन्हें लेकर कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। अभी तक यूपीएस से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार, एनपीएस से भी ज्यादा खराब है। इसमें शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाले बेसिक पे व डीए के वेतन का 10वां भाग, सरकार कटौती के नाम पर ले रही है।

सपा अध्यक्ष को भी पत्र

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया था, उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। पत्र में अध्यक्ष एसएन पाठक और महासचिव श्रीकुमार ने कहा, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ, जो 3.5 लाख रक्षा असैन्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, वह एक जनवरी 2004 से लागू हुई सबसे भयावह और अनुचित नई पेंशन योजना के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहा है। पिछले 24 वर्षों से केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी, एनपीएस का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के नाम से यूपीएस की घोषणा की है, जो एनपीएस का संशोधित संस्करण है। इस अनुचित यूपीएस को सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है। एआईडीईएफ ने यूपीएस का विरोध किया है। श्रीकुमार ने लिखा, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी इस योजना पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए यूपीएस का खारिज कर दिया है। इस अनुचित यूपीएस योजना के खिलाफ इंडिया अलायंस के कई सांसदों ने इसे एनपीएस का अनुचित संस्करण बताया है। ऐसे समय पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपीएस की निंदा की है। उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की है कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में वापस आता है तो वे एनपीएस/यूपीएस को खत्म कर देंगे। ओपीएस बहाल की जाएगी। इस बयान के लिए एआईडीईएफ ने यादव का आभार व्यक्त किया है।

देशभर में चल रहा संवाद

नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल भी ओपीएस बहाली के लिए जुट गए हैं। वे देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कर्मचारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने आगरा में कर्मचारियों से बातचीत की है। आने वाले दिनों में वे दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के आयोजन करेंगे। डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने यूपीएस में कई सुधारों की मांग की है। पत्र में मुख्य तौर पर पांच मांगों का जिक्र किया गया है। अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जाए, ताकि केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भी न्याय मिल सके। दूसरी मांग, रिटायरमेंट/वीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाए, ताकि बुढ़ापे में कर्मचारी अपने पैसे से बेटी के हाथ पीले कर सके। घर बनवा सके, तीर्थ यात्रा कर सके और स्वाभिमान पूर्वक जीवन जी सके।

वीआरएस के लिए अनिवार्य सेवा 20 वर्ष की जाए

वीआरएस के लिए भी 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा की जगह 20 वर्ष की जाए। यह नियम, केंद्र के ओपीएस में शामिल कर्मचारियों के लिए लागू है। इससे दोनों कर्मचारियों के बीच समानता के अधिकार के कानून का पालन हो सकेगा। ऐसा न होने से एक विसंगति पैदा हो गई है। इसके चलते कोर्ट केस बढ़ेंगे। वीआरएस लेने वाले कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से ही 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन देने की व्यवस्था की जाए न कि रिटायरमेंट डेट से। यहां पर सोचने वाली बात है कि यूपीएस में कैबिनेट का निर्णय है कि वीआरएस लेने वाले व्यक्ति को पेंशन, रिटायरमेंट तिथि यानी 60 साल की उम्र के बाद ही दी जाएगी। बतौर पटेल, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार उस व्यक्ति को वीआरएस के बाद दस साल तक कोई पेंशन नहीं देगी। अगर इस बीच रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष तक बढ़ा दी गई तो उसे 15 साल तक कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर सरकार यह कैसे निर्धारित कर पाएगी कि वीआरएस लेने वाला व्यक्ति, हर हाल में पेंशन लेने के लिए 60 या 65 वर्ष तक जीवित ही रहेगा। एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए।

जन हितैषी

तत्काल न्याय संवैधानिक नहीं तानाशाही का परिचायक

हाल के वर्षों में बुलडोजर, जेसीबी, और अब हाइड्रा मशीनें भारत के कुछ राज्यों में अपराधियों के खिलाफ त्वरित न्याय कार्रवाई का प्रतीक बन गई हैं। इस त्वरित न्याय प्रणाली का उपयोग अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। तथाकथित अपराध के नाम पर संपत्तियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में विशेष रूप से देखी गई है। इस तरह की कार्रवाई को तत्काल न्याय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस तरह की कार्रवाई को शुरुआत में जनता द्वारा सराही गई। यह उन माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कसने का प्रतीक मानी गई, जो लंबे समय से कानून की जद से बाहर थे। कई राज्य सरकारों द्वारा पिछले कुछ महीनो से एक व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध मे एक समुदाय विशेष, अल्पसंख्यकों को लक्षित कर तुरंत न्याय के रूप में बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है। आरोप है कि किसी घटना के बाद अपराधी के घर और उसकी संपत्तियों को अवैधानिक अतिक्रमण मानते हुए बिना उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना निर्दोष लोगों अथवा परिवार के अन्य सदस्यों को जिनका अपराध से कोई लेना-देना नहीं था, उनको भी शिकार बनाया गया है।

बुलडोजर संस्कृति की न्याय व्यवस्था में एक व्यक्ति के अपराध का दंड पूरे परिवार या समुदाय को भुगतना पड़ रहा है। एक किराएदार द्वारा किए गए अपराध के लिए मकान मालिक की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह की कार्रवाइयों के पीछे अवैध निर्माण का हवाला देकर बिना उचित नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियों को गिराया गया, जिससे यह सवाल उठता है, कि क्या यह वास्तविक न्याय है, या प्रतिशोध की राजनीति?अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के अधिकार प्रशासन और पुलिस ने अपने हाथ में ले लिए हैं। कुछ मामलों में न्यायालय में आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अदालत ने निर्दोष बरी कर दिया गया। किन्तु प्रशासन ने उसके परिवार को बेघर कर दिया। लाखों रूपये का मकान गिरा दिया। अपराधी को कई दिनों तक जेल में बंद रखा। सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म कर दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में हस्तक्षेप किया है, लेकिन अभी तक इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई ठोस कदम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं उठाया गया है। संविधान और कानून की परवाह किए बिना प्रशासनिक ताकतों द्वारा मनमानी और तानाशाही करने का यह स्पष्ट उदाहरण है। संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का हनन कई राज्य सरकारों द्वारा खुले आम किया जा रहा है। यह देश की न्याय व्यवस्था और संविधान पर गहरी चोट है। संविधान और न्यायपालिका को अपना अस्तित्व बनाए रखना है, ऐसी स्थिति में इस तरह की त्वरित न्याय प्रणाली को बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर सख्त रुख अपनाना होगा। ऐसे सभी मामलों में जहां बिना उचित न्यायिक प्रक्रिया के अभाव में बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। उन्हें न्याय दिलाना न्याय पालिका की जिम्मेदारी है। जिन परिवारों और जिन व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। उन लोगों को संबंधित राज्य सरकार और संबंधित प्रशासकीय अधिकारियों से मुआवजा दिलवाया जाए। जिनकी संपत्ति और सम्मान को बिना किसी ठोस आधार के ध्वस्त कर संवैधानिक अधिकारों को असंवैधानिक तरीके से खत्म किया गया है। स्वतः संज्ञान लेकर न्यायपालिका तत्काल न्याय की प्रवृत्ति पर रोक लगाए। न्यायपालिका सुनिश्चित करे, शासन और प्रशासन कानून का पालन करें, नाकि उसका दुरुपयोग हो। दंड और प्रशासकीय प्रक्रिया का पालन संविधान एवं कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना ही लोकतंत्र की सच्ची पहचान है, इसे किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं किया जा सकता। किसी एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरे परिवार अथवा एक समुदाय को नहीं दी जा सकती है। भारत में लोकशाही का राज है, तानाशाही का नहीं, इस बात को ध्यान में रखना होगा। तानाशाही में ना तो प्रजा सुरक्षित रहती है, नाही राजशाही से जुड़े हुए पदाधिकारी सुरक्षित रहते हैं। तानाशाही केवल तानाशाह को सुरक्षित बनाती है। तानाशाही तब तक सुरक्षित रहती है। जब तक जनता इसका विरोध नहीं करती है। जब जनता विरोध में सड़कों पर उतरकर आती है। तो बड़े से बड़े तानाशाह का अस्तित्व कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बुलडोजर संस्कृति और त्वरित न्याय के नाम पर जो हो रहा है, वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस सारी कार्यवाही में जो भी दोषी हों, उन्हें दंडित किए जाने की जरूरत है। आशा है, समय रहते न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेगी। कई वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले लंबित पड़े हुए हैं। जिसके कारण त्वरित न्याय संस्कृति बड़ी तेजी के साथ एक प्रदेश से कई प्रदेशों तक फैल गई है। आंध्र प्रदेश मैं तुरंत न्याय के नाम पर अब बुलडोजर के साथ-साथ हाईवा जैसी मशीनों का उपयोग हो रहा है। यह सरकारों एवं प्रशाकीय अधिकारियों का आतंक है, इस पर जितनी जल्दी नियंत्रण लगाया जाए, उतना ही भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहतर होगा।

आत्मा के उन्नयन एवं उत्कर्ष महापर्व-पर्युषण

(पर्युषण महापर्व (31 अगस्त से 7 सितम्बर 2024) पर प्रकाशनार्थ)

जैनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है पयुर्षण पर्व। यह पर्व ग्रंथियों को खोलने की सीख देता है। इस आध्यात्मिक पर्व के दौरान कोशिश यह की जाती है कि जैन कहलाने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन को इतना मांज ले कि वर्ष भर की जो भी ज्ञात-अज्ञात त्रुटियां हुई हैं, आत्मा पर किसी तरह का मैल चढ़ा है वह सब धुल जाए। संस्कारों को सुदृढ़ बनाने और अपसंस्कारों को तिलांजलि देने का यह अपूर्व अवसर है। इस पर्व में श्वेताम्बर परम्परा में आठ दिन एवं दिगम्बर परम्परा में दस दिन इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का प्रयत्न करता है। ये दिन नैतिकता और चरित्र की चौकसी का काम करते हैं और व्यक्ति को प्रेरित करते हैं वे भौतिक और सांसारिक जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाएं।

आत्मोत्थान तथा आत्मा को उत्कर्ष की ओर ले जाने वाले इस महापर्व की आयोजना प्रतिवर्ष चातुर्मास के दौरान भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष में की जाती है। इस महापर्व में निरंतर धर्माराधना करने का प्रावधान है। इन दिनों जैन श्वेतांबर मतावलंबी पर्युषण पर्व के रूप में आठ दिनों तक ध्यान, स्वाध्याय, जप, तप, सामायिक, उपवास, क्षमा आदि विविध प्रयोगों द्वारा आत्म-मंथन करते हैं। दिगंबर मतावलंबी दशलक्षण पर्व के रूप में दस दिनों तक इस उत्सव की आराधना करते हैं। क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग तथा ब्रह्मचर्य इन दस धर्मो के द्वारा अंतर्मुखी बनने का प्रयास करते हैं। जो आदमी के जीवन की सारी गंदगी को अपनी क्षमा आदि दस धर्मरूपी तरंगों के द्वारा बाहर करता है और जीवन को शीतल एवं साफ-सुथरा बनाता है। जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, तब प्रायः आग पैदा होती है। ऐसा ही आदमी के जीवन में भी घटित होता है। जब व्यक्तियों में आपस में किन्हीं कारणों से टकराहट पैदा होती है, तो प्रायः क्रोधरूपी अग्नि भभक उठती है और यह अग्नि न जाने कितने व्यक्तियों एवं वस्तुओं को अपनी चपेट में लेकर जला, झुलसा देती है। इस क्रोध पर विजय प्राप्त करने का श्रेष्ठतम उपाय क्षमा-धारण करना ही है। पर्युषण पर्व का प्रथम 'उत्तम क्षमा' नामक दिन, इसी कला को समझने, सीखने एवं जीवन में उतारने का दिन होता है।

इसी तरह अहंकार आदमी के अंतःकरण में उठते हैं। इसी अहंकार के कारण आदमी पद और प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है, जो उसे अत्यंत गहरे गर्त में धकेलती है। पर्युषण पर्व का द्वितीय 'उत्तम मार्दव' नामक दिवस, इसी अहंकार पर विजय प्राप्त करने की कला को समझने एवं सीखने का होता है। जैन मनीषियों ने कहा है कि सुख और शांति कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही हैं और अपने घर में प्रवेश पाने के लिए वक्रता या टेड़ेपन को छोड़ना परम अनिवार्य है, जैसे सर्प बाहर तो टेड़ा-मेड़ा चलता है, पर बिल में प्रवेश करते समय सीधा-सरल हो जाता है, वैसे ही हमें भी अपने घर में आने के लिए सरल होना पड़ेगा। सरल बनने की ही कला सिखाता है 'उत्तम आर्जव धर्म।' हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूपी पांचों पापों के वशीभूत होकर प्राणी दिन-रात न्याय और अन्याय को भूलकर धन आदि के संग्रह में सत्य को धारण करने वाला हमेशा अपराजित, सम्माननीय एवं श्रद्धेय होता है। दुनिया का सारा वैभव उसके चरण चूमता है। यह सब 'उत्तम सत्य धर्म' की ही महिमा है।

जैसे किसी भी वाहन को मंजिल तक सही-सलामत पहुंचाने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है, वैसे ही कल्याण के पथ पर चलने वाले प्रत्येक पथिक के लिए संयम की परम आवश्यकता होती है। इंद्रिय एवं मन को जो सुख-इष्ट होता है, वह वैषयिक सुख कहलाता है। जो मीठे जहर की तरह सेवन करते समय तो अच्छा लगता है, पर उसका परिणाम दुःख के रूप में ही होता है। ऐसे दुःखदायक वैषयिक सुख से 'उत्तम संयम धर्म' ही बचाता है। अज्ञानता एवं लोभ-लिप्सा के कारण जीव, धन, संपत्ति आदि को ग्रहण करता है। ये ही पदार्थ दुःख, अशांति को बढ़ाने का कारण बनते हैं। ऐसे पर पदार्थों को छोड़ना ही 'उत्तम त्याग धर्म' कहलाता है। जब कोई साधक क्रोध, मान, माया, लोभ एवं पर पदार्थों का त्याग आदि करते हैं और इनसे जब उनका किंचित भी संबंध नहीं रहता तो उनकी यह अवस्था स्वाभाविक अवस्था कहलाती है। इसे ही 'उत्तम आकिंचन्य धर्म' कहा गया है। पर-पदार्थों से संबंध टूट जाने से जीव का अपनी आत्मा जिसे ब्रह्म कहा जाता है में ही रमण होने लगता है। इसे ही 'उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म' कहा जाता है। ये ही धर्म के दस लक्षण हैं, जो पर्युषण पर्व के रूप में आकर न केवल जैनों को, अपितु समूचे प्राणी-जगत को सुख-शांति का संदेश देते हैं। पर्युषण की आराधना के इन दिनों में व्यक्ति अपने आपको शोधन एवं आत्मचिंतन के द्वारा वर्षभर के क्रिया-कलापों का प्रतिक्रमण प्रतिलेखन करता है।

विगत वर्ष में हुई भूलों को भूलकर चित्तशुद्धि का उपाय करता है। सभी व्यक्ति एक दूसरे से क्षमा का आदान-प्रदान करते हैं, जिससे मनोमालिन्य दूर होता है और सहजता, सरलता, कोमलता, सहिष्णुता के भाव विकसित होते हैं। पर्युषण पर्व एवं दसलक्षण पर्व के आयोजनों के साथ मुख्य रूप से तप और मंत्र साधना को जोड़ा गया है। संयम, सादगी, सहिष्णुता, अहिंसा, हृदय की पवित्रता से हर व्यक्ति अपने को जुड़ा हुआ पाता है और यही वे दिन हैं जब व्यक्ति घर और मंदिर दोनों में एक सा हो जाता है। छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं का उत्साह दर्शनीय होता है। आहार-संयम, उपवास एवं अठाई तप के द्वारा इस महापर्व को मनाते हैं। इस अवसर पर जैन मंदिरों, स्थानकों, उपासना स्थलों, जिनालयों की रौनक बढ़ जाती है। संपूर्ण जैन समाज में साधु-साध्वियों, उपासकों, विद्वत्जनों के प्रवचनों के द्वारा धर्म की विशेष आराधना होती है। श्रावक-श्राविकाएं भी अपना धार्मिक दायित्व समझकर अध्यात्म की ओर प्रयाण करते हैं। अनेक स्थानों पर इन दिनों व्यापारिक गतिविधियां सीमित हो जाती हैं। कई प्रतिष्ठान विशेष दिनों के आयोजन पर अवकाश भी रखते हैं। श्रेष्ठीजन अपने कर्मचारियों को भी धर्माराधना हेतु प्रेरित करते हैं।

पयुर्षण पर्व में क्षमा, मैत्री, करुणा, तप, मंत्र साधना आदि पर विशेष बल दिया जाता है। क्षमा का सर्वाधिक महत्व इस पर्व के साथ जुड़ा है- मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, सब जीव मुझे क्षमा करते हैं। मेरी सब प्राणियों से मित्रता है, किसी से मेरा वैर-भाव नहीं है। प्रभु महावीर के इस मैत्री मंत्र के साथ सामूहिक क्षमापना-क्षमावाणी दिवस को समूचा जैन समाज विश्व मैत्री दिवस के रूप में मनाता है। पर्युषण पर्व एक प्रेरणा है, पाथेय है, मार्गदर्शन है और अहिंसक जीवन शैली का प्रयोग है। आज भौतिकता की चकाचौंध में, भागती जिंदगी की अंधी दौड़ में इस पर्व की प्रासंगिकता बनाये रखना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जैन समाज संवेदनशील बने विशेषतः युवा पीढ़ी पर्युषण पर्व की मूल्यवत्ता से परिचित हो और वे सामायिक, मौन, जप, ध्यान, स्वाध्याय, आहार संयम, इन्द्रिय निग्रह, जीवदया आदि के माध्यम से आत्मचेतना को जगाने वाले इन दुर्लभ क्षणों से स्वयं लाभान्वित हो और जन-जन के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करे। पर्युषण महापर्व मात्र जैनों का पर्व नहीं है, यह एक सार्वभौम पर्व है। पूरे विश्व के लिए यह एक उत्तम और उत्कृष्ट पर्व है, क्योंकि इसमें आत्मा की उपासना की जाती है। संपूर्ण संसार में यही एक ऐसा उत्सव या पर्व है जिसमें आत्मरत होकर व्यक्ति आत्मार्थी बनता है व अलौकिक, आध्यात्मिक आनंद के शिखर पर आरोहण करता हुआ मोक्षगामी होने का सद्प्रयास करता है। प्रस्तुतिः ललित गर्ग (लेखक- देवेन्द्र ब्रह्मचारी / ईएमएस) (प्रख्यात जैन संत देवेन्द्र ब्रह्मचारी जन आरोग्यम फाउण्डेशन के संस्थापक है।)

पर्यावरण सरंक्षण के उपाय

पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दो से मिलकर बना है – ''परि'' और ''आवरण'' अर्थात वह आवरण जो हमें चारों और से घेरे हुआ है उसे पर्यावरण कहते है। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वाराराजनैतिकऔर सामाजिक जाग्रति लाने के लिये घोषित किया गया है। सबसे पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था।पर्यावरण मेजैविक जैसे कि जीवाणु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधों से लेकर हमसभी इंसान शामिल है। जबकि अजैविक तत्वों में निर्जीव तत्व जैसे पर्वत, चट्टानें नदी आदि शामिल हैं।मनुष्य द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाएँ पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।विज्ञान के क्षेत्र मे असीमित प्रगति का असर पर्यावरण पर पड़ा है। आज मानव विज्ञान के क्षेत्र में नये-नये आविष्कार कर रहा है। लेकिन इन आविष्कारों के कारण वह प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। धरती पर जनसंख्या वृद्धि का असर भी पर्यावरण पर रहा है।औद्योगीकरण तथा शहरीकरण की तीव्र गतिप्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त कर रही है। हमारी प्रथ्वी पर पेड़-पौधे, हवा, पानी है तो हम है।आज इंसान प्रथ्वी पर बहुत ज्यादा अन्याय कर रहा है। दुनिया कंक्रीट की होती जा रही है। पेड़-पौधे काटे जा रहें हैं। जिसके कारणवर्षा कम हो गयी है, सूखा पड़ रहा है। आजधरती पर सबसे बड़ी समस्या जल की है। आज हमें बारिश के पानी को संग्रहित करने की आवश्यकता है। इसके लिये हमें बड़े स्तर पर तालाब, पोखर बनाने की जरुरत है। आजकल वाटर मेंनेजमेंट को लेकर कई संस्थान बहुत सारे कोर्सेस चला रहें हैं। जिसमे वाटर साइंटिस्ट, वाटर मेंनेजर, हाइड्रो जियोलाजिस्ट, बायोलाजिस्ट, वाटर कंजरबेशनिस्ट आदि बनाने के मौके बढ़ गए हैं।आज प्रदूषण के कारण सारी धरती प्रदूषित हो रही है और ऐसा ही रहा तो मानव सभ्यता का अंत निश्चित है। पर्यावरण प्रदूषण के बहुत से दुष्प्रभाव है जो अत्यंत घातक है; जैसे परमाणु विस्फोटो से वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओज़ोन परत का क्षतिज होना, मृदा क्षरण आदि। पर्यावरण सरंक्षण को ध्यान में रखते हुए 1992 मे ब्राज़ील में एक 'पृथ्वी सम्मेलन' आयोजित किया गया जिसमे विश्व के 174 देशों ने हिस्सा लिया। इसके बाद सन 2002 में जोहान्सवर्ग में प्रथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें पर्यावरण सरंक्षण पर अनेक उपाय सुझाए गए।हमें अपने पर्यावरण को बेहतर बनाना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें जल को बचाना पड़ेगा। फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में न जाये इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कारखानों का गंदा पानी सीवर लाइन के गंदे पानी को नदियों में जाने से रोकना होगा, जिससे की हम इंसान और समस्त प्राणीजगत गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से बच सकें। प्रदूषित पानी को हम अपनी खेती में न डालें।हमें अपने बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा पर समुचित ज्ञान समय-समय पर देते रहना चाहिए। उनको पर्यावरण के बारे में जानकारी दे।जल प्रदूषण के साथ-साथ वायु प्रदूषण ने भी हमारे पर्यावरण को बहुत हानिपहुंचाई हैं। बड़े-बड़े कारखानों की चिमनियों से निकले गंदे धुए, ए।सी। इनवर्टर, जैनरेटर आदि से निकली कार्बन डाइआक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसे वायुमंडल में घुलती रहती है। जिससे की हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता रहता है।ध्वनि प्रदूषण भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। बच्चे के जन्म की खुशी, शादी पार्टी आदि में डी।जे। आवश्यक हो ग??या है इन सभी ध्वनि प्रदूषण से भी हमारी धरती प्रदूषित हो रही है।आज समूचा विश्व जलसंकट की समस्या से गुजर रहा है। आज हमें जल को संग्रहित करने के लिये बड़े स्तर पर वाटर हारवेस्टिंग, कंजबेशन और मेंनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिससे कि पानी को हम संग्रहित कर सकें तथा संग्रहित किया गया जल हमारी खेती के काम आ सके।हमने जो धरती से लिया है वह धरती को वापस करना पड़ेगा अगर नहीं किया तो धरती पर असंतुलन पैदा हो जायेगा। (लेखिका- डॉ अंकिता मिश्रा / ईएमएस)

अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम चर्चा में ....

सरकार ने करोड़ों सेवानिवृत्त लोगों के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा पेंशन को नई यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लाकर फिर चर्चा में ला दिया है। सरकार इसे ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) और न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के बीच का कर्मचारी हितैषी मार्ग बता कर पेश कर रही है तो विपक्ष यूटर्न पेंशन स्कीम कहकर इसका मजाक उड़ा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में पेंशन प्रचार के प्रमुख बिंदुओं में से एक थी और संभवतः इसने चुनाव परिणाम काफी हद तक प्रभावित कर भाजपा को स्पष्ट बहुमत पाने से रोक दिया था। इसीलिए चर्चा है की सरकार ने यह योजना महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनावी फायदे के लिए लागू की है। बहरहाल यह नहीं भूलना चाहिए कि ओपीएस लागू करने के बावजूद कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान पिछला विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार चुकी है।

2004 के पूर्व अंतिम आहरित वेतन के आधे के बराबर पेंशन की गारंटी वाली ओपीएस में कर्मचारी अंशदान जरूरी नहीं था। संपूर्ण व्यय सरकारी कंधों पर था। निरंतर बढ़ते पेंशन व्यय को संतुलित करने के लिए 2004 से लागू एनपीएस में कर्मचारियों और सरकार का 10 प्रतिशत समान अंशदान अनिवार्य कर दिया गया। 2019 में सरकारी अंशदान मूल वेतन और डीए का 14 प्रतिशत कर दिया गया.

यह राशि भविष्य के पेंशन भुगतान के लिए शेयर मार्केट समेत अन्य वित्तीय संसाधनों में लगाने का प्रावधान था। कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय विकल्पों के बीच चुनने का अधिकार तो था मगर इसमें इन वित्तीय विकल्पों का सीमित ज्ञान बाधक था। यह पेंशन मार्केट के उतार-चढ़ाव के आधार पर परिवर्तनीय थी। इसमें शामिल कर्मचारी हाल के सालों में रिटायर होने लगे हैं और शिकायत है कि उनकी पेंशन कभी 100 तो कभी 120 रुपये प्रतिमाह होती है, ऐसे में वे ज़िंदगी कैसे बिताएं। बनारस के एक कॉलेज के प्रिंसिपल क़रीब डेढ़ लाख की सैलरी थे पर पेंशन 4,044 बनी। यही वजह है कि इसे रद्द कर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग जोरों पर थी।

सरकार ने अपने चिर परिचित अंदाज में नई पेंशन योजना पर भी कर्मचारी संगठनों से विमर्श जरूरी नहीं समझा। नयी योजना में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी कुल संयोजित राशि का 60 प्रतिशत निकाल सकते हैं। बाकी 40 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और निजी कंपनियों द्वारा प्रमोट किए गए पेंशन फ़ंड मैनेजर्स की विभिन्न स्कीमों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रैच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर हर छह महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का दसवें हिस्से के बराबर एकमुश्त रक़म देने का प्रावधान भी है। नई योजना के कई प्रावधानों पर ओपीएस लागू कराने की मांग कर रहे कर्मचारी संगठन नाराज हैं। कर्मचारी के अपने अंशदान को निकालने को लेकर प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। यूपीएस में फुल पेंशन के लिए 25 साल की सीमा तय है इसलिए अर्द्धसैनिक बलों समेत 25 साल की सेवा के पूर्व रिटायर हो जाने वाले अनेक कर्मचारी इस फायदे से बाहर हो गए हैं। सेवा के दौरान मृत्यु पर आधा वेतन पेंशन के रूप में मिलने का प्रावधान भी अस्पष्ट है। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर यह नई पेंशन योजना इतनी ही प्रभावी और हितकारी है तो इसे सांसदों और विधायकों के लिए लागू क्यों नहीं किया जा रहा।

देश के अन्य करोड़ों सेवानिवृत्त लोगों पर लागू कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े रिटायर्ड लोगों की न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए किए जाने की मांग अलग लंबित है। इसकी वर्तमान न्यूनतम राशि इतनी कम है कि खुद सरकारी मापदंडों के आधार पर दो जून की रोटी का इंतजाम असंभव है। संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पेंशन राशि में वृद्धि समेत उनके और जीवनसाथी के लिए पूर्ण चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग भी रखी गई है। विरोध प्रदर्शन कर रहे पेंशनभोगी पिछले आठ वर्षों से प्रतीक्षारत हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।

पेंशन को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण घटक वेतन पुनरीक्षण भी है। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। पिछले आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं अतः नया वेतन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 से देय है। सातवें वेतन आयोग के गठन और वास्तविक वेतन पुनरीक्षण में दो साल के लगभग समय लगा था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा को दी गई जानकारी के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए उसे 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान में आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सांसदों विधायकों के लाभों संबंधी निर्णय प्राथमिकता के आधार पर लेने वाली सरकार कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण पर कतई गंभीर नहीं दिखाई देती।

दो साल पहले आई सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आजादी के बाद लोगों की औसत आय दुगनी होकर 70 वर्ष हो जाने से बुजुर्गो की संख्या निरंतर बढ़ रही है। वहीं बच्चों द्वारा बुजुर्ग माता पिता की देखभाल का सामाजिक ताना बाना ऐसा छिन्न-भिन्न हो रहा है कि सरकार को बुजुर्ग माता पिता की देखभाल पर विवश करने के लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं। बेलगाम महंगाई, निरंतर बढ़ता चिकित्सा खर्च और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर हो रही कमी बुजुर्गो की दुश्वारियां बढ़ा रहा है। सरकार का आलम यह है कि सहानुभूति तो छोड़िए, स्वास्थ्य बीमा की प्रीमियम राशि पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाए बैठी है। कुल मिलाकर लगता है कि देश में बूढ़ा होना अपराध बनता जा रहा है। बुजुर्गों के पास चुपचाप सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने के अलावा सिवाय और कोई चारा नहीं है। (लेखक- चैतन्य भट्ट/ ईएमएस)

आरक्षण का राजनीतिकरण देशहित में कदापि नहीं

देश जब आजाद हुआ तो सामाजिक समरसता के लिये सामाजिक, आर्थिक, एवं शैक्षणिक रूप से अति पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु संविधान में आरक्षण देने का प्रावधान सीमित काल के लिये किया गया पर यह राजनीतिकरण के चलते आज तक जारी हीं नहीं इसका विस्तार होता गया। आरक्षण वोट की राजनीति से जुड़ गया। आरक्षित वर्ग में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से विकास होने के वावजूद भी इसमें कोई परिर्तन नहीं हुआ बल्कि अनुसूचित जाति, जनजाति के अलावे देश की कई जातियां आरक्षण के दायरे में समा गई। इस दिशा में उभरे राजनीतिकरण को आसानी से देखा जा सकता जब सत्ता की कुर्सी पाने के लिये मंडल आयोग को देश में लागू करने की वकालत की गई। जिसके तहत पिछड़े वर्ग ओबीसी नाम से देश की कई जातियां आरक्षण सूचि में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ता पाने के लिये राजस्थान प्रदेश में जाट वर्ग को ओबीसी में शामिल करने की वकालत तत्कालीन राजनीतिक दल भाजपा द्वारा किया गया जिसका राजनीतिक लाभ भी मिला, केन्द्र में सरकार बनते ही राजस्थान के जाट वर्ग को ओबीसी में शामिल भी कर लिया गया। आरक्षण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सुधार की जगह लाभ तंत्र का संसाधन बन गया। इस दिशा में बढ़ते राजनीतिकरण ने अनारक्षित अन्य जातियों को भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण में शामिल किये जाने की वकालत राजनीतिक दलों द्वारा की जाने लगी। कुछ राज्यों में इस दिशा में पहल भी हुई। इस तरह देश में आरक्षण का अनुपात 50 प्रतिशत से भी आगे चला गया। आरक्षण जिसे मिल गया वो किसी भी कीमत पर इससे अलग होने को तैयार नहीं।

इस दिशा में सर्वेक्षण भी यहीं बता रहे है रहे है कि वास्तविक रूप से आरक्षण आरक्षित वर्ग में जिसे मिलना चाहिए वह आज भी आरक्षण प्रक्रिया से दूर है। इस कमी को दूर करने के लिये हीं देश की सर्वोच्य न्यायालय ने आरक्षण में क्रीमीलेयर लाने की पहल की जिससे आरक्षित वर्ग में आरक्षण से वंचित सर्वाधिक लोगों को आरक्षण प्रक्रिया से जोड़ा जा सके पर सर्वोच्य न्यायालय के इस पहल पर जो विवाद देश भर में खड़ा हुआ, सभी के सामने है।

आरक्षित वर्ग में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़े हुये को आरक्षण प्रक्रिया से दूर कर देना चाहिए पर वोट की राजनीति से जुड़े इस मसले पर पहल कौन करे। सर्वोच्य न्यायालय ने पहल की तो विवाद खड़ा हो गया। इसे लेकर भी देश में राजनीति शुरु हो गई। सभी को वोट चाहिए। वोट से जुड़ा आरक्षण समाप्त तो नहीं किया जा सकता पर देशहित में जरूरी है कि आरक्षण का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। आरक्षण का जातिगत आधार की जगह आर्थिक आधार होना चाहिए। इस दिशा में सभी राजनीतिक दलों को विचार कर पहल करना होगा। (लेखक- - डा. भरत मिश्र प्राची)

शब्द पहेली - 8115

बाएँ से दाएँ

1. कृष्ण का एक नाम-4,3
6. धन,संपत्ति-2
7. इस युवती को बयान बदलने पर जेल की सजा हुई है-3
8. विजय, फतह-2
10. आम जनता,लोग-2
11. लाभ,कुल योग-2
13. निर्माण, कृति-3
14. उत्तर-3
15. नष्ट, विनाश-2
17. रुस्तमे हिंद का सिर्फ नाम-2
18. तह, अस्तर-2
20. राजी होना-3
21. अवरोध, रुकावट-2
22. आतंक फैलना-4,3

ऊपर से नीचे

2. भिड़ंत, मुठभेड़-3
3. इस्लामी महीना-4
4. हाथी, गज-4
5. न्यायाधीश-2
6. जोरदार-5
9. लालसी, आकांक्षी, पिपासु-5
10. स्त्रीत्वपूर्ण, स्त्रीय-3
12. वृतांत, घटना-3
16. हल, निष्कर्ष-4
17. राशन, भोजन-4
19. घोड़ा गाड़ी-2
21. रुकावट, अवरोध-3

शब्द पहेली -8114 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

टी20 में पहले विकेट के लिए अनुज-सुजल ने ठोके 241 रन, नया रिकॉर्ड बनाया

नई दिल्ली,(ईएमएस)। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में ईस्ट दिल्ली और पुरानी दिल्ली 6 के बीच मुकाबले के दौरान टी20 में पहले विकेट के लिए 241 रन बनाकर अनुज रावत और सुजल सिंह ने रिकॉर्ड बनाया है। इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके रावत और सुजल ने प्रतिद्वंद्वी टीम के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते हुए शतक ठोके।

पहले विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ टी20 भागीदारी का रिकॉर्ड जापान के लाचलान यामामोटो लेक (134 रन) और केंडेल कादोवाकी फ्लेमिंग (109 रन) के नाम है जिन्होंने इस साल फरवरी में चीन के खिलाफ 20 ओवर में 258 रन की साझेदारी की थी। अनुज ने 66 गेंद में 11 छक्के और छह चौकों के साथ 121 रन बनाए जबकि सुजल ने 57 गेंद में 9 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 108 रन बनाए। इस 242 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली 6 निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 215 रन ही बना सकी और 26 रन से हार गई।

एटकिंसन ने लॉर्ड्स में श्रीलंका के खिलाफ ठोंका पहला टेस्ट शतक

नई दिल्ली (ईएमएस)। इंग्लिश गेंदबाज गस एटकिंसन ने लॉर्ड्स में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है। एटकिंसन ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन उपलब्धि हासिल की। पहले दिन 74 रन बनाकर नाबाद थे और इंग्लैंड 358/7 रन ही बना सका। दूसरे दिन एटकिंसन ने अपने शॉट्स से लंकावासियों को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने सुंदर ऑफ-ड्राइव के साथ शतक पूरा किया। एटकिंसन लॉर्ड्स में टेस्ट शतक और 10 विकेट लेने वाले छठे खिलाड़ी बने हैं। वह गब्बी एलन (इंग्लैंड), कीथ मिलर (ऑस्ट्रेलिया), इयान बॉथम (इंग्लैंड), स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड) और क्रिस वोक्स (इंग्लैंड) की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

एटकिंसन जब क्रीज पर आए उस समय इंग्लैंड का स्कोर 216/6 था। उन्होंने मैथ्यू पॉट्स के साथ 85 रन की साझेदारी की। फिर रूट के साथ 92 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। उनकी पारी में कई करारे शॉट शामिल रहे। एटकिंसन ने दूसरे दिन चौकों की झड़ी लगाकर शुरुआत की। जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले एटकिंसन ने उस श्रृंखला में 14.66 की औसत से 44 रन बनाए थे।

एटकिंसन शतक (नंबर 8 या उससे नीचे) लगाने वाले छठे खिलाड़ी

169 - स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड) बनाम पाकिस्तान, 2010

122 - गुब्बी एलन (इंग्लैंड) बनाम न्यूजीलैंड, 1931

121 - बर्नार्ड जूलियन (वेस्टइंडीज) बनाम इंग्लैंड, 1973

118 - गस एटकिंसन (इंग्लैंड) बनाम श्रीलंका, 2024

113 - रे इलिंगवर्थ (इंग्लैंड) बनाम वेस्टइंडीज, 1969

109* - अजीत अगरकर (भारत) बनाम इंग्लैंड, 2002

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

श्रीलंका : दिमुथ करुणारत्ने, पथुम निसांका, निशान मदुष्का (विकेटकीपर), एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चंडीमल, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, मिलन प्रियनाथ रथनायके

इंग्लैंड : बेन डकेट, डैनियल लॉरेंस, ओली पोप (कप्तान), जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, मैथ्यू पॉट्स, ओली स्टोन, शोएब बशीर।

पेरिस पैरालिंपिक : निशानेबाजी में पिछड़े मनीष नरवाल

नई दिल्ली (ईएमएस)। टोक्यो खेलों के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज मनीष नरवाल ने पेरिस पैरालिंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल (एसएच1) स्पर्धा में रजत पदक जीतने से पहले कड़ी टक्कर दी।

नरवाल ने टोक्यो में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, काफी समय तक बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन खराब स्कोर के कारण पिछड़े और अनुभवी दक्षिण कोरियाई निशानेबाज जो जोंगडू के सामने बढ़त हासिल कर ली। भारतीय पिस्टल निशानेबाज शिवा नरवाल के बड़े भाई नरवाल ने 234.9 का स्कोर किया, जबकि जोंगडू ने 237.4 के कुल स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता।

इसके पहले अवनि लेखरा महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल (एसएच1) स्पर्धा में जीत के साथ दो पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। वहीं इसी प्रतियोगिता में उनकी हमवतन मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। भारत ने अब तक पैरालंपिक में चार पदक अपने नाम कर लिए हैं।

इस युवा बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ शतक लगाकार, ठोंक दी दावेदारी

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय युवा स्टार साई सुदर्शन ने इंग्लिश काउंटी में सेंचुरी लगाकर खलबली पैदा कर दी है। अपने पहले ही सीजन में सर्रे की तरफ से खेलने उतरे 22 साल से युवा खिलाड़ी ने छक्के से शतक ठोका। नॉटिंघमशर के खिलाफ खेली गई पारी के बाद लोग उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुनी जाने वाली टीम के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस के लिए कमाल दिखाने वाले साई की पारी के दम पर सर्रे ने पहली पारी में 525 रन बनाए। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सभी चयनकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए भारत की घरेलू टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे अनुभवी खिलाड़ी बुची बाबू टूर्नामेंट में उतरे हैं। वहीं युवा साई सुदर्शन ने काउंटी क्रिकेट का रुख किया है।

भारत के उभरते खिलाड़ी साई सुदर्शन ने काउंटी क्रिकेट में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए दमदार शतक जमाया। 178 बॉल का सामना करते हुए साई ने 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 105 रन की पारी खेली। पारी का एक मात्र छक्का उन्होंने शतक तक पहुंचने के लिए लगाया। 237 मिनट तक मैदान पर वक्त बिताकर इस बैटर ने भारत की आगामी बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए दावेदारी ठोकी है। साई सुदर्शन ने भारत के लिए अब तक 3 वनडे और 1 टी20 इंटरनेशनल खेला है। दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस बैटर ने वनडे डेब्यू किया था। जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें टी20 डेब्यू करने का मौका मिला था। अपने पहले दोनों ही वनडे में साई सुदर्शन ने अर्धशतक जमाया था। पहले मैच में नाबाद 55 रन बनाए जबकि दूसरे मुकाबले में 62 रन की पारी खेली थी।श्रीलंका दौरे पर चुनी गई वनडे टीम में साई सुदर्शन को जगह नहीं मिली थी।

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में यशस्वी पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को लगाना होगा अंकुश : बुकानन

सिडनी (ईएमएस)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मुख्य कोच जॉन बुकानन ने भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल की जमकर प्रशंसा की है। बुकानन के अनुसार यशस्वी एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में उनपर अंकुश लगाना आसान नहीं होगा। इस पूर्व कोच के अनुसार अगर यशस्वी अपनी लय में रहे तो हमारे लिए सीरीज पर कब्जा करना कठिन रहेगा। साथ ही कहा कि अगर उनका बल्ला चला तो भारतीय टीम का सीरीज में पलड़ा भारी हो जाएगा। पूर्व कोच के अनुसार इस युवा भारतीय बल्लेबाज को खेलते हुए देखना रोमांचक होता है। उसने हालांकि अब तक ऑस्ट्रेलियाई मैदानों पर नहीं खेला है।

यशस्वी के नाम अभी 9 टेस्ट मैचों में 1028 रन हैं जिसमें तीन शतक शामिल हैं। उनका 5 दिवसीय क्रिकेट में 68.53 का औसत है। वह दो दोहरे शतक और चार अर्धशतक लगा चुके हैं। इस बल्लेबाज ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इंग्लैंड के भारत दौरे में इस बल्लेबाज ने 5 मैचों और 9 पारियों में 79.91 की स्ट्राइक रेट से 712 रन बनाकर सीरीज में सबसे अधिक रन बनाये थे, इसमें दो दोहरे शतक और तीन अर्द्धशतक शामिल थे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज 22 नवंबर से पर्थ में पहले टेस्ट के साथ शुरू होगी। वहीं एडिलेड ओवल में 6 से 10 दिसंबर तक होने वाला दूसरा टेस्ट दिन-रात प्रारूप में खेला जाएगा। इसके बाद, प्रशंसकों का ध्यान तीसरे टेस्ट के लिए ब्रिस्बेन के गाबा पर होगा, जो 14 से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। मेलबर्न के मशहूर मेलबर्न क्रिकेट मैदान में 26 से 30 दिसंबर के बीच पारंपरिक बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा। वहीं 3 से 7 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट मैदान में 5वां और अंतिम टेस्ट खेला जाएगा।

आरबीआई के नाम से कॉल आए तो सतर्क रहें, नहीं तो साफ हो जाएगा बैंक खाता

नई दिल्ली (ईएमएस)। आरबीआई के नाम से कोई भी फोन कॉल आए तो सतर्क हो जाएं, केंद्रीय बैंक ने अपनी कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर करने से साफ मना किया है। बैंक ने साइबर क्रिमिनल्स के ठगी करने के तरीकों को भी बताया। साइबर ठग आरबीआई के फर्जी लेटर हेड या ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। खुद को केंद्रीय बैंक कर्मचारी बताते हैं। यूजर को भारी भरकम लॉटरी जीतने या सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनने जैसे लालच देकर फंसाते हैं। फिर उनका अकाउंट साफ कर देते हैं। आरबीआई के मुताबिक कई बार जालसाज खुद को सरकार या फिर केंद्रीय बैंक का अधिकारी बनकर संपर्क करते हैं। उनसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या योजना की आड़ में सिक्योरिटी डिपॉजिट करने को कहते हैं। जालसाज कई बार डरा-धमकाकर भी ठगी की कोशिश करते हैं।

इसमें पीड़ितों से कॉल, एसएमएसया मेल के जरिए संपर्क किया जाता है। उनके अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक करने की धमकी दी जाती है। उन्हें कुछ फर्जी किस्म के लिंक से ऐप भी डाउनलोड करने के लिए बहकाया या मजबूर किया जाता है। इसके जरिए यूजर्स की कई निजी जानकारियां उन ठगों के हाथ लग जाती है। आरबीआई का कहना है कि यूजर्स को अपनी कोई भी निजी जानकारी दूसरों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। किसी भी बैंक या बैंक कर्मचारी को यूजर्स से फोन या ईमेल के जरिए ओटीपी या कोई अन्य जानकारी मांगने की इजाजत नहीं है। अगर कोई शख्स फोन कर खुद को सरकारी अधिकारी या बैंक कर्मचारी बताकर ऐसी जानकारी मांगता है, तो तत्काल इसकी शिकायत पुलिस को करनी चाहिए।

कनाडा में केएफसी ने ऐसा क्या किया कि........हिंदुओं, सिखों ने भेज दिया नोटिस

टोरंटो (ईएमएस)। केंटुकी फ्राइड चिकन (केएफसी) ने ओंटारियो में अपने अधिकांश रेस्तरां में हलाल-प्रमाणित चिकन परोसने और हराम (इस्लामिक कानून द्वारा निषिद्ध) पोर्क उत्पादों को बंद करने की योजना की घोषणा के बाद खुद को कनाडा में विवाद में ला दिया है। अमेरिकी फास्ट-फूड चेन केएफसी का लक्ष्य इस्लामी आहार कानूनों का पालन करके ग्राहकों को अधिक विविध और समावेशी विकल्प देना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदलाव मई में शुरू हुआ था। कनाडा के सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय के घर, ओंटारियो प्रांत के सभी केएफसी स्टोरों को कवर किया। वहीं अब कनाडा के हिंदुओं, सिखों ने हलाल मांस पर केएफसी को नोटिस दिया है।

हिंदू फोरम कनाडा ने नोटिस भेजकर केएफसी से क्रूरता, कानून की भावना और समावेश के सिद्धांतों के खिलाफ होने का हवाला देकर फैसले को पलटने के लिए कहा है। वे हलाल मांस परोसे जाने के विचार के विरोध में नहीं हैं, बल्कि केवल यह तर्क देते हैं कि रेस्तरां को उन धर्मों से संबंधित लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-हलाल मांस भी परोसना चाहिए जहां हलाल निषिद्ध है।

नोटिस में कहा कि लगभग 71 वर्षों से केएफसी ने ओंटारियो में रेस्तरां का संचालन इस शर्त के बिना किया है कि उसके प्रत्येक रेस्तरां में केवल हलाल चिकन ही परोसा जाए। हमारा मानना है कि यह अचानक परिवर्तन कानून की भावना, समावेशिता के सिद्धांत, या आपके स्वयं के कॉर्पोरेट ब्रांड के अनुरूप नहीं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अखंडता और कड़ी मेहनत का प्रतीक है।

भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करता है तो संबंध हो सकते हैं खराब

-आलमगीर बोले-अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश का आंतरिक मामला

ढाका,(ईएमएस)। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में नया अध्याय शुरू करने के लिए पूर्व पीएम शेख हसीना का प्रत्यर्पण जरूरी है। उन्होंने कहा कि हसीना की भारत में मौजूदगी से द्विपक्षीय संबंध और खराब कर सकती है।

बीएनपी महासचिव ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर अवामी लीग शासन के दौरान हुए विवादास्पद अडाणी बिजली समझौते की समीक्षा करेगी। क्योंकि इससे बांग्लादेश के लोगों पर तबाही भरा दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने भारत के साथ मजबूत संबंधों की इच्छा जताई है और कहा कि उनकी पार्टी पिछले मतभेदों को पीछे छोड़कर सहयोगी रवैया अपनाने को तैयार है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बीएनपी बांग्लादेश की धरती पर भारत की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं देगी।

आलमगीर ने तर्क दिया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश का आंतरिक मामला है और हिंदुओं पर हमलों की रिपोर्टें निश्चित रूप से गलत हैं क्योंकि अधिकांश घटनाएं राजनीतिक प्रेरित होती हैं। आलमगीर का मानना है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करना भारत-बांग्लादेश संबंधों को और खराब कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश सौंप देना चाहिए ताकि बांग्लादेशी लोगों की भावनाओं का सम्मान हो सके।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत की बांग्लादेश कूटनीति उचित नहीं है और इसे बांग्लादेश के लोगों और अन्य के साथ संबंध स्थापित करने की जरूरत है, न कि अकेले अवामी लीग के साथ। अगर बीएनपी सत्ता में आई, तो वह भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने और पिछले मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करेगी। बीएनपी नेता ने कहा कि शेख हसीनाऔरअवामीलीग दोनों ही बांग्लादेश में आलोचना के योग्य हैं, और ये उनका समर्थन करने से भारत की छवि और बिगड़ेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अगर भारत ने शेख हसीना को समर्थन दिया, तो इससे सिर्फ भारत के प्रति बांग्लादेश में नाराजगी बढ़ेगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचेगा देश का यूपीआई सिस्टम : दास

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) कई और देशों तक बढ़ेगा। गवर्नर दास ने कहा कि यूपीआई पहले ही क्यूआर कोड और फास्ट पेमेंट सिस्टम के जरिये कई देशों में मौजूद है और कई अन्य देशों के साथ इस पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि यह वैश्विक स्तर पर और बढ़ेगा और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचेगा। दास ने कहा था कि इस दिशा में पहले से ही भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, मॉरीशस, नामीबिया, पेरू, फ्रांस और कुछ अन्य देशों के साथ उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से दुनिया भर में भारत की पहलों को अपनाने के लिए सकारात्मक रुख का पता चलता है।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा

नईदिल्ली (ईएमएस)। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नवरत्न का दर्जा दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ?हाल ही में एक बयान में यह जानकारी दी। गौरतलब है ?कि कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एसईसीआई एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। मंत्रालय के मुताबिक एसईसीआई एक अग्रणी सीपीएसई है जो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता के विकास और विस्तार के लिए समर्पित है, जिसमें 69.25 गीगावॉट उत्पादन की क्षमता है। यह प्रतिवर्ष 42 बिलियन यूनिट से ऊपर की व्यापार करती है तथा जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और सतत विकास के लिए प्रयास करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 20.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 13,118.68 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 34.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए कर के पश्चात 510.92 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है।

रूस में एमआई-8टी हेलिकॉप्टर लापता

क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे, झील में गिरने की आशंका

मास्को (ईएमएस)। रूस का एमआई-8टी हेलिकॉप्टर उड़ान के दौरान लापता हो गया है। इसके हादसे का शिकार हो जाने की आशंका है। हेलिकॉप्टर जिस वक्त लापता हुआ, उस वक्त उसमें तीन क्रू के सदस्यों समेत कुल 22 लोग सवार थे। रूस की एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कहा कि हेलिकॉप्टर ने कामचटका इलाके में वाचकाझेट्स ज्वालामुखी के पास एक साइट से 25 किमी दूर स्थित निकोलेवका के लिए उड़ान भरी थी। हेलिकॉप्टर झील में गिर गया। ये मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से पर्यटकों को लेकर जा रहा था। भारतीय समय के मुताबिक हेलिकॉप्टर को 9 बजकर 30 मिनट पर बेस पर लौटना था लेकिन लौटकर नहीं आया। क्रू मेंबर्स से संपर्क करने की कोशिश की गई मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बचावकर्मी लापता हेलिकॉप्टर की तलाश में जुट गए हैं। हेलिकॉप्टर की खोज के लिए एक अन्य एयरक्राफ्ट को भेजा गया है। जिस इलाके में हेलिकॉप्टर लापता हुआ, वहां बूंदाबांदी और कोहरा देखा गया।

केदारनाथ में रिपेयर के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा हेलिकॉप्टर गिरा

- बैलेंस बिगड़ा तो पायलट ने घाटी में ड्रॉप किया

केदारनाथ (ईएमएस)। केदारनाथ से गौचर के बीच भीमबली के पास रिपेयर के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा एक हेलिकॉप्टर घाटी में गिर गया। इसे वायुसेना के एमआई-17 से एयरलिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन हवा के असर और हेलिकॉप्टर के वजन से बैलेंस बिगड़ने लगा। पायलट ने सूझ बूझ के साथ उसे घाटी में ड्रॉप कर दिया। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है।

दरअसल, केस्ट्रल एविएशन का एक हेलिकॉप्टर 24 मई को खराब हो गया था। इसमें 6 यात्री सवार थे। हेलिकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग से पहले हवा में 8 बार लहराया था। तभी से यह हेलीपैड पर खड़ा था। इसकी गौचर एयरबेस पर रिपेयरिंग होनी थी।

हेलिकॉप्टर में न तो कोई यात्री था, न सामान, इसलिए किसी तरह के जान-माल के नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ऐहतियातन एसडीआरएफ के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर हेलिकॉप्टर के मलबे में सर्चिंग की।

क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिरता देख लोगों में चीख-पुकार ही मच गई। बताया जा रहा है कि इस क्षतिग्रस्त हेली के सभी जरूरी पार्ट पहले ही निकाल दिए गए थे। वहीं इस हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए वायु सेना के एमआई-17 हेलिकॉप्टर की मदद से हैंग करके गौचर हवाई पट्टी पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इस दौरान एमआई -17 अचानक ही डिसबैलेंस होने लगा।

मिस्त्र और ग्रीस के विदेश मंत्रियों ने मध्य पूर्व में जारी हिंसा को लेकर बातचीत की

काहिरा (ईएमएस)। मिस्त्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती और ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस के बीच मध्य पूर्व में जारी हिंसा को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मध्य पूर्व में अस्थिरता को बढ़ने से रोकने के प्रयासों पर जोर दिया गया। मिस्त्र के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि फोन पर बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों ने मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम, खासकर गाजा पट्टी की स्थिति पर चर्चा की। मिस्त्र के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा ?कि दोनों मंत्रियों ने शुक्रवार को फोन पर बातचीत के दौरान मध्य पूर्व में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम की गंभीरता पर चर्चा की। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अब्देलती ने ग्रीस के विदेश मंत्री को बताया कि मिस्त्र इस क्षेत्र के कई देशों, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के साथ संपर्क कर रहा है, ताकि क्षेत्रीय तनाव और वृद्धि की मौजूदा स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। ग्रीस के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर मिस्त्र और ग्रीस के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है। बयान में कहा गया कि दोनों मंत्रियों ने क्षेत्र के लोगों के हित में परामर्श और समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई है। इससे पहले मिस्त्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती और कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली के बीच गाजा में युद्ध विराम को लेकर चर्चा हुई थी। मिस्त्र के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि फोन पर बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों ने मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम, खासकर गाजा पट्टी की स्थिति पर चर्चा की। साथ ही युद्ध विराम पर भी जोर दिया। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अब्देलती ने मध्य-पूर्व देशों में जारी तनाव को रोकने और गाजा में युद्ध विराम का समाधान निकालने के लिए मिस्त्र के प्रयासों की समीक्षा की।

कोरोना के बाद प्रॉपर्टी पंजीकरण में वरिष्ठ लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी

मुंबई (ईएमएस)। मुंबई में 61 वर्ष और उससे अधिक की आयु वर्ग के लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी में 204 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को ?मिली है। जुलाई 2024 तक यह आंकड़ा 15,276 है, जो 2020 में 7,554 पर था। कुल प्रॉपर्टी पंजीकरण में वरिष्ठ लोगों की हिस्सेदारी 2023 में बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है, जो कि 2020 में 12 प्रतिशत थी। एक रिपोर्ट में बताया कि 2023 में वरिष्ठ नागरिकों की ओर से 22,849 प्रॉपर्टी का पंजीकरण कराया गया था। 2024 में जुलाई तक यह आंकड़ा 15,276 था। रिपोर्ट में बताया कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कराए जाने वाले प्रॉपर्टी पंजीकरण की संख्या इस साल 23,000 जाने की उम्मीद है। प्रॉपर्टी खरीद बढ़ने की वजह 2020 के बाद लाइफस्टाइल में बदलाव आना है। ?रिपोर्ट में बताया गया है ?कि कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम का चलन तेजी से बढ़ा है। इससे महामारी ने परिवारों को एकजुट किया है, जिसके कारण बड़े घरों की मांग में इजाफा हुआ है।

आतंकवादी समूहों के साथ आई एस आई की निर्विवाद मिलीभगत

पूर्व अमेरिकी एनएसए मैकमास्टर का खुलासा

वाशिंगटन (ईएमएस)। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एचआर मैकमास्टर ने अपनी पुस्तक में कहा कि आतंकवादी समूहों के साथ पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) की निर्विवाद मिलीभगत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ट्रम्प प्रशासन के दौरान अपने कार्यकाल का प्रत्यक्ष विवरण देकर मैकमास्टर ने पुस्तक में दावा किया है कि तत्कालीन रक्षा सचिव जिम मैटिस एक सैन्य सहायता देने की योजना में थे। इस्लामाबाद को पैकेज जिसमें 150 मिलियन मूल्य के बख्तरबंद वाहन शामिल थे, मैकमास्टर के हस्तक्षेप के बाद वह सहायता रोक दी गई।

मैकमास्टर ने लिखा है कि कुछ गतिविधियों को रोकने के लिए ट्रम्प के निर्देशों का पालन करना भी राज्य और रक्षा के लिए मुश्किल था। जब मैटिस ने इस्लामाबाद का दौरा किया, तब उन्हें पता चला कि यह दक्षिण एशिया रणनीति के विपरीत है, जिसमें कुछ अपवादों के साथ पाकिस्तान को सभी सहायता को निलंबित करने का आह्वान किया गया था। पेंटागन एक सैन्य सहायता पैकेज देने जा रहा था जिसमें 150 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के बख्तरबंद वाहन शामिल थे।

पूर्व एनएसए ने लिखा कि उन्होंने मैटिस, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के उप निदेशक जीना हास्पेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई, जहां उन्होंने कहा कि ट्रंप कई मौकों पर पाकिस्तानियों को सहायता बंद करने के लिए बहुत स्पष्ट थे। उन आतंकवादी संगठनों के लिए समर्थन जो अफगानिस्तान में अफगानों, अमेरिकियों और गठबंधन के सदस्यों को मार रहे थे। मैटिस ने गौर किया कि पाकिस्तान कुछ खास तरीकों से जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत डेविड हेल सहित अन्य लोगों ने इस बात को साझा नहीं किया। मैटिस ने अनिच्छा से सहायता का शिपमेंट रोक दिया लेकिन अन्य सहायता जारी रही।नतीजतन, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पिछले 15 वर्षों में पाकिस्तान को मूर्खतापूर्ण तरीके से 33 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता दी है और उन्होंने हमारे नेताओं को मूर्ख समझकर हमें झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है।

मैकमास्टर ने लिखा कि पाकिस्तान ने अपना व्यवहार नहीं बदला और मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी हाफिज सईद को रिहा किया, जो अमेरिका के लिए अपमान सरीखा था।

शेयर बाजार में निवेशकों की संपत्ति 9 दिन में 10 लाख करोड़ बढ़ गई

नई दिल्ली (ईएमएस)। शेयर बाजार में नौ दिनों की तेजी के दौरान निवेशकों की संपत्ति 10 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और घरेलू निवेशकों की खरीदारी के समर्थन के बीच बाजार में तेजी रही। नौ दिनों की तेजी में बीएसई बेंचमार्क 1,941.09 अंक चढ़ा। लगातार नौवें सत्र में शुक्रवार को तेजी के साथ 30 शेयरों वाला बीएसई का बेंचमार्क सेंसेक्स 231.16 अंक चढ़कर 82,365.77 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ।

बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण नौ कारोबारी दिनों में 10,00,028 करोड़ रुपये बढ़कर 4,64,39,993.77 करोड़ रुपये (5.54 हजार अरब डॉलर) हो गया। बाजार के जानकारों ने कहा ?कि व्यापक आधार पर खरीदारी के समर्थन के कारण बेंचमार्क सूचकांकों ने सकारात्मक कारोबारी सत्र में नई ऊंचाई को छुआ, क्योंकि पिछले सप्ताह जैक्सन होल बैठक के बाद अगले महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने निवेशकों की धारणा को और सकारात्मक कर दिया है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल और पावर ग्रिड सबसे ज्यादा लाभ में रहीं। दूसरी ओर, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा और आईटीसी घाटे में रहीं।

गृहयुद्ध से तबाह हुआ सूडान, एक लाख से ज्यादा लोग मारे गए

-भूख और कुपोषण से गई करीब 25 लाख लोगों की जान, लाखों लोग दूसरे देशों में शरण लेने को हुए मजबूर

खारतून,(ईएमएस)। सूडान में जारी गृहयुद्ध ने एक गंभीर मानवीय संकट को जन्म दिया है, जिससे लाखों लोग जीवन-मरण की स्थिति का सामना कर रहे हैं। देश की राजधानी खारतूम और अन्य प्रमुख शहरों में तबाही फैल चुकी है, और 1.5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

सूडान की इस भयावह स्थिति ने लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया है। देश के भीतर शरणार्थी शिविरों में 80 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं, जबकि एक करोड़ से अधिक लोग पड़ोसी देशों में शरण लेने पर मजबूर हो चुके हैं।

सूडान में खाद्य संकट इतना गंभीर हो चुका है कि लोग घास और पत्ते खाने को मजबूर हो गए हैं। फसलें जल चुकी हैं, और अकाल का खतरा मंडरा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल के अंत तक 25 लाख लोग भूख और कुपोषण के कारण अपनी जान गंवा सकते हैं। इसके अलावा, डच थिंक टैंक के एक विश्लेषण के अनुसार, यदि सूडान में खाद्य पदार्थों की कमी बनी रहती है, तो 2027 तक 60 लाख से एक करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। यह विश्व के सबसे भयानक मानवीय संकटों में से एक बन गया है।

इस संकट में कई बाहरी देशों की भूमिका भी रही है। विद्रोही गुट रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) पर सामूहिक दुष्कर्म और जनसंहार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, और संयुक्त अरब अमीरात आरएसएफ को गोला-बारूद और ड्रोन जैसी सैन्य सामग्री की आपूर्ति कर रहा है। वहीं, ईरान और मिस्त्र सरकार समर्थक सूडान आर्म्ड फोर्सेस (एसएएफ) को हथियार दे रहे हैं। रूस भी इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि उसके वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिक दोनों पक्षों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा, सऊदी अरब, तुर्किये और कतर जैसे देश इस संघर्ष में अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाने की होड़ में हैं।

इस युद्ध का प्रभाव सूडान के पड़ोसी देशों चाड, मिस्त्र, इथियोपिया और लीबिया पर भी पड़ रहा है, जहां शरणार्थियों और लड़ाकू गुटों की आवाजाही जारी है। अफ्रीका के अलावा, मध्य पूर्व और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी इस संकट का असर देखा जा सकता है। शरणार्थियों के यूरोप जाने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं, जिससे यूरोपीय देशों को भी इस संघर्ष के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

सूडान की स्थिति पर दुनिया का ध्यान अपेक्षाकृत कम रहा है, खासकर गाजा और यूक्रेन के संकटों की तुलना में। इसके बावजूद, सूडान में हो रही त्रासदी ने वैश्विक स्तर पर एक गंभीर चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस स्थिति का समाधान नहीं किया गया, तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जिनेवा में चल रही युद्धविराम वार्ता से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है, और अगर यह स्थिति जारी रही, तो सूडान का संकट और भी भयानक हो सकता है।

क्विबोलोय के आश्रम में छापेमारी सेक्स स्लेव के लिए बना तहखाना

मनीला (ईएमएस)। फिलीपींस में एक विवादास्पद धार्मिक नेता अपोलो क्विबोलोय के आश्रम पर पुलिस ने छापा मारा, छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुद को ईश्वर का पुत्र कहने वाले क्विबोलोय के आश्रम में एक गुप्त मार्ग का पता चला, जो कथित तौर पर सेक्स स्लेव के लिए बनाए गए तहखाने तक जाता था। तहखाने में एक भव्य लाउंज मिला, जिसका दरवाजा ऐसा था कि वह दीवार जैसा दिखता था। इस 75 एकड़ के विशाल परिसर में रास्ते भूलभुलैया की तरह हैं, पुलिस को छापेमारी में आश्रम में संदिग्ध गतिविधियों का पता चला।

क्विबोलोय, जो फिलीपींस के दावो सिटी से ताल्लुक रखते हैं, पर कई जघन्य अपराधों में शामिल होने का आरोप है। उनकी किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट चर्च नामक संस्था के 60 लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं। अमेरिका में भी क्विबोलोय पर धोखाधड़ी और बच्चों की यौन तस्करी में शामिल होने के आरोप हैं। पुलिस ने बड़े ऑपरेशन के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया था। एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छापा मारकर पुलिस ने दो महिलाओं को बचाया, जिन्हें कथित तौर पर सेक्स स्लेव के रूप में बंदी बनाकर रखा गया था। इसके अलावा, पुलिस को संदेह है कि परिसर के अंदर और भी कई कट्टरपंथी अनुयायी छिपे हो सकते हैं, जिनका पता लगाने के लिए रडार का इस्तेमाल हो रहा है।

आंतरिक सचिव बेनहुर अबालोस ने कहा कि सरकार दावो सिटी के इंजीनियरिंग कार्यालय से आश्रम का नक्शा प्राप्त कर रही है ताकि निर्माण नियमों के उल्लंघन की जांच की जा सके। हालांकि, क्विबोलोय ने सभी आरोपों से इनकार कर शैतान के एजेंटों की साजिश बताया है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी एफबीआई ने आरोप लगाया था कि क्विबोलोय ने महिलाओं को निजी सहायक या पादरी के रूप में काम करने के लिए भर्ती किया, जिनसे घर के काम, मसाज, और रात में यौन संबंध बनाने जैसे काम करवाए जाते थे। इस क्विबोलोय नाइट डयूटी कहता था।

हालांकि, पुलिस की छापेमारी के बाद क्विबोलोय ने खुद को निर्दोष बताकर कानून का सामना करने की बात कही, लेकिन इसके बाद वह अचानक से गायब हो गया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस बीच, क्विबोलोय के समर्थक इस छापेमारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जिसमें अब तक 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और 6 पुलिस वाले घायल हुए हैं।

पेरिस पैरालंपिक : भारतीय खिलाड़ियों ने चार मेडल जीतकर लहराया परचम

-अवनि लेखरा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर रच दिया इतिहास

पेरिस,(ईएमएस)। हाल ही खत्म हुए पेरिस ओलिंपिक्स में भारत ने पूरे छह मेडल जीते थे जिसमें गोल्ड मेडल नहीं था लेकिन, पेरिस पैरालिंपिक्स में दूसरे दिन ही भारत के पैरा-ऐथलीटों ने शानदार खेल का मुजाहिरा कर एक ही दिन में चार मेडल जीत लिए हैं। इसमें भारत की मशहूर शूटर वंडर गर्ल अवनि लेखरा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है।

भारत पदक तालिका में 10वें नंबर पर है। खास बात यह है कि पैरालिंपिक्स में जो चार मेडल भारत को मिले हैं उसमें तीन देश की बेटियों ने जीते हैं। अवनि लेखरा पैरालिंपिक में दो गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं हैं। उन्होंने टोक्यो के बाद पेरिस पैरालिंपिक्स में भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल (एसएच1) स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है वहीं भारत की ही मोना अग्रवाल को ब्रॉन्ज मेडल जीता है।

तीन साल पहले टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतने वाली 22 साल की अवनि ने 249.7 का स्कोर करके अपना ही 249.6 का पुराना रेकॉर्ड तोड़ा है। वहीं शॉटपुट, पावरलिफ्टिंग और व्हीलचेयर वॉलिबॉल के बाद दो साल पहले शूटिंग में पदार्पण करने वाली मोना ने 228.7 के स्कोर कर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत के पैरालिंपिक्स इतिहास में पहली बार दो शूटर्स ने एक ही इवेंट में मेडल जीते हैं। अवनि अब 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस में उतरेंगी जिसमें वह मेडल की प्रबल दावेदार हैं। पिछली बार टोक्यो में इस स्पर्धा में उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया था।

जयपुर की रहने वाली अवनि पैरालिंपिक्स से पहले स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। उनकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई जिस कारण उन्हें डेढ़ महीने ब्रेक लेना पड़ा था। सर्जरी की वजह से उनका काफी वजन भी कम हुआ। उन्होंने पेरिस पैरालिंपिक्स में भारत का परचम लहराया दिया है। उन्होंने कहा कि वह देश के लिए मेडल जीतकर खुश हूं। अपनी टीम, कोचों और अपने परिवार को थैंक्स कहना चाहती हूं।

अवनि और मोना के अलावा पुरुषों में भारत के मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल (एसएच 1) स्पर्धा में सिल्वर जीता। नरवाल के बड़े भाई मनीष ने 234.9 स्कोर किया जबकि जियोंगडू ने 237.4 स्कोर करके गोल्ड जीता। एसएच-1 वर्ग में खिलाड़ी बिना किसी दिक्कत के पिस्टल उठा सकते हैं और व्हीलचेयर या चेयर पर से खड़े होकर या बैठकर निशाना लगाते हैं।

पैरालिंपिक्स के दूसरे दिन प्रीति पाल ने भी महिलाओं की टी35 वर्ग की 100 मीटर स्पर्धा में 14.21 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय से ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को पहला ऐथलेटिक्स मेडल दिलाया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया-भारत के लिए एक और गौरव का पल, प्रीति पाल ने पैरालिंपिक्स में 100 मीटर टी35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। उन्हें बधाई। यह सफलता निश्चित रूप से उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। अवनि ने कहा कि मुकाबला काफी मुश्किल था, लेकिन वह जीती। इसलिए शुक्रिया। अवनि के साथ रहने से मदद मिली। वह एक चैंपियन हैं और वह मुझे प्रेरित करती हैं। मोना अग्रवाल ने कहा कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैंने मेडल जीता है। मैं फक्र महसूस कर रही हूं कि मैंने पैरालिंपिक्स में भारत का पहला ट्रैक मेडल जीता है।

आखिरकार मस्क की मदद से वापस आएगी सुनीता विलियम्स

वाशिंगटन (ईएमएस)। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को अगले साल फरवरी में धरती पर वापस लाया जाएगा। इसके लिए ऐलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल की मदद ली जा रही है। यह क्रू-9 मिशन है, जिसकी लॉन्चिंग 24 सितंबर 2024 को होगी। पहले इसमें चार एस्ट्रोनॉट्स जा रहे थे। अब सिर्फ दो ही जाएंगे। ताकि लौटते वक्त सुनीता और बुच को ला सकें।

पहले के तय प्लान में मिशन की कमांडर जेना कार्डमैन थीं। पायलट निक हेग, मिशन स्पेशलिस्ट स्टेफनी विल्सन और रूसी कॉस्मोनॉट मिशन स्पेशलिस्ट एलेक्जेंडर गोरबुनोव जा रहे थे। लेकिन अब इसमें सिर्फ दोनों पुरुष एस्ट्रोनॉट्स यानी रूसी एस्ट्रोनॉट और एलेक्जेंडर गोरबुनोव और पायलट निक हेग जाएंगे।

पहले के मिशन पायलट निक हेग अब मिशन के कमांडर है। एलेक्जेंडर के प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं है। क्रू-9 मिशन के ड्रैगन कैप्सूल को स्पेस स्टेशन से डॉक करने के लिए पहले वहां जगह बनाई जा रही है। बोईंग के खराब स्टारलाइनर को 6 सितंबर की देर रात सवा तीन बजे के करीब अनडॉक किया जाएगा। वहां कैप्सूल 7 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे धरती पर लौटेगा। इसके बाद ड्रैगन उसकी जगह पर डॉक होगा।

यह नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है। स्पेस एक्स के साथ मिलकर स्पेस स्टेशन का 9 रोटेशनल मिशन है। ताकि स्पेस स्टेशन पर लगातार रिसर्च होती रहे। दुनिया को मौसम की सही जानकारी मिलती रहे।

क्या है ड्रैगन कैप्सूल, जो लाएगा सुनीता को स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू कैप्सूल अपने बनने के बाद से अब तक 46 बार लांच हो चुका है। 42 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है। 25 बार रीफ्लाइट हुई है। इस कैप्सूल में एक बार में सात एस्ट्रोनॉट्स के बैठने की व्यवस्था है। यह दुनिया का पहला निजी स्पेसक्राफ्ट है, जो लगातार स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो लेकर आता-जाता रहा है। खाली कैप्सूल का वजन 7700 किलोग्राम होता है।

जब यह कार्गो और एस्ट्रोनॉट्स के साथ लांच किया जाता है, तब इसकी अधिकतम वजन क्षमता 12,500 किलोग्राम होती है। यह किसी ऑर्बिट में 6000 किलोग्राम वजन पहुंचा सकता है।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लाई डिटेक्टर टेस्ट में हुए रोचक खुलासे

नई दिल्ली (ईएमएस)। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का मजेदार लाई डिटेक्टर टेस्ट किए गए, इसमें रोचक खुलासे हुए। शो में क्रिकेटर ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, मिशेल मार्श, पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा और जोश हेजलवुड मौजूद रहे। टेस्ट के दौरान सभी क्रिकेटरों से सवाल पूछे गए। सही जवाब देने पर नीली बत्ती जली, जबकि गलत जबाव देने पर लाल। इस दौरान खिलाड़ियों को बिजली का हलका झटका भी लगता था। टेस्ट के दौरान मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई ऑलराऊंडर ग्लेन मैकसवेल के लिए रोचक खुलासा भी कर गए।

दरअसल, मेजबानों ने इससे ख्वाजा ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैक्सवेल जब गोल्फ कार्ट से गिरे (विश्व कप 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ चूक गए थे) थे तब वहां कोई कवर-अप था। इस पर ख्वाजा ने कहा कि नहीं! क्योंकि मैं वहां था। मैंने गाड़ी से गिरते हुए देखा। लेकिन तब उस झटका लगा, जो खेल के नियमों के अनुसार झूठ था। बता दें कि मैक्सवेल इंग्लैंड के खिलाफ 2023 क्रिकेट विश्व कप मैच में अपनी टीम से चूक गए थे। रिपोर्टों के अनुसार, मैक्सवेल फिसल गए और गाड़ी के पीछे से गिर गए, जिससे उनके सिर में चोट लग गई, जिसके कारण उन्हें इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया। इस दौरान मिशेल मार्श ने भी मैक्सवेल पर रोचक खुलासा करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराऊंडर अपने दांतों का नया सेट लेने के लिए तुर्की गए थे।

वहीं, ट्रैविस हेड से पूछा गया कि क्या उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 2023 वनडे विश्व कप जीत के बाद 35 से अधिक बियर पी थी। इस पर स्टार बल्लेबाज ने नहीं में उत्तर दिया। उन्हें बिजली का झटका लगा। टेस्ट में लाबुशेन से उनके नाम के सही उच्चारण के बारे में पूछा गया। वहीं, ख्वाजा से जब क्या डेविड वॉर्नर के बिना मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम का माहौल बेहतर है? सवाल पूछा गया तब उन्होंने नहीं में उत्तर दिया, लेकिन लाल बत्ती जल उठी।

बलूचिस्तान में हुआ आतंकी हमला एससीओ बैठक के खिलाफ एक साजिश

पाकिस्तानी गृह मंत्री बोले-सम्मेलन के आयोजन से कुछ को हो रही तकलीफ

इस्लामाबाद,(ईएमएस)। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि बलूचिस्तान में हाल में हुए आतंकवादी हमलों की साजिश पाकिस्तान में होने एससीओ शिखर बैठक को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई थी। नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन में बलूचिस्तान की स्थिति पर कहा कि देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले तत्वों से निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। इस दौरान पाकिस्तानी गृह मंत्री ने बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधा और कहा कि बहुत लोग हैं जो एससीओ सम्मेलन के आयोजन से उन्हें तकलीफ हो रही हैं।

बता दें पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दो दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस्लामाबाद ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। नकवी ने सदन को बताया, हमें स्पष्ट लिंक मिले हैं, जो बताते हैं कि इसके पीछे कौन है। आतंकवादियों ने एससीओ सम्मेलन को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। 26 अगस्त का हमला शिखर सम्मेलन के खिलाफ एक साजिश थी।

हिंसा की हालिया घटना में बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने प्रांत में कई हमले किए, जिसमें 14 सुरक्षाबलों समेत कम से कम 50 लोग मारे गए। गृह मंत्री नकवी ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में हमले की योजना सिर्फ एक संगठन ने नहीं बनाई थी, बल्कि आतंकवादी संगठनों ने इसे मिलकर अंजाम दिया था। नकवी ने अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया और कहा, जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार करते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग राज्य को स्वीकार नहीं करते और हथियार उठाते हैं, वे आतंकवादी हैं और हम उनसे निपटेंगे।

गुजरात में पीएम जन-धन योजनांतर्गत लाभार्थियों की संख्या 1.87 करोड़ के पार, 1 करोड़ 41 लाख से अधिक रुपे कार्ड जारी किए गए

गांधीनगर (ईएमएस) भारत के लोगों की सुख-सुविधा में वृद्धि के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने अनेक विकासोन्मुखी योजनाएँ लागू की हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना 10 वर्ष पूर्व हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, जिसने देश के लोगों को सशक्त बनाने में मील के पत्थर समान योगदान दिया है। यह योजना यानी प्रधानमंत्री जन-धन योजना। पिछले 10 वर्षों में वित्तीय समावेशन के इस राष्ट्रीय मिशन का अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिला है और हाल में 53 करोड़ से भी अधिक लोग मूलभूत वित्तीय सेवाओं का लाभ ले रहे हैं।

गुजरात में प्रधानमंत्री जन-धन योजना अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 1.87 करोड़ के पार हो गई है और इन जन-धन खातों में 9,681 करोड़ रुपए से भी अधिक बैलेंस दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार इस योजना का लाभ गुजरात के अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुँचाने के निरंतर प्रयास कर रही है।

पीएम जन-धन योजनांतर्गत लाभार्थियों की संख्या 10 वर्ष में 53 करोड़ के पार :प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने 28 अगस्त, 2014 को देश के सभी लोगों को बैंक खाते, ऋण, भुगतान, बचत व पूंजी, क्रेडिट, बीमा व पेंशन आदि मूलभूत सेवाएँ सरलता से मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या 10 वर्ष में 53 करोड़ के पार हो गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें आधे से अधिक खाते देश की नारी शक्ति के हैं। देश जन-धन खातों में अब कुल बैलेंस 2,31,235 करोड़ रुपए हो गया है। इस योजनांतर्गत 11.58 लाख बैंकमित्रों द्वारा देश में शाखा रहित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

पीएम जन-धन : विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहली :प्रधानमंत्री जन-धन योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन गई है। इस योजना के कारण अनेक लोगों के लिए बैंक सुविधा उपलब्ध हुई है। विशेषकर; गरीब लोगों को सस्ती दर पर रेमिटेंट्स, क्रिडेट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, सेविंग्स तथा डिपॉजिट अकाउंट्स आदि विभिन्न वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध हुई हैं। गुजरात में 1.87 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खुले :गुजरात में पीएम जन-धन योजना अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 1.87 करोड़ से भी अधिक हो गई है। ग्रामीण तथा सेमी-अर्बन सेंटर की बैंक शाखाओं में लाभार्थियों की संख्या 1,12,35,605 है; जबकि शहरी-मेट्रो सेंटर की बैंक शाखाओं में यह संख्या 75,28,872 है। अर्थात् राज्य में इस योजना के कुल 1,87,64,477 लाभार्थी हैं। इन लाभार्थियों के खातों में 9,681 करोड़ रुपए से भी अधिक बैलेंस है और इस योजना के तहत 1,41,91,805 रुपे कार्ड जारी किए गए हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत कौन खुलवा सकता है खाता ? :पीएम जन-धन योजनांतर्गत भारत निवासी 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी नागरिक जन-धन खाता खुलवा सकता है। जन-धन खाता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अलावा निजी बैंकों में भी खुलवाया जा सकता है। यदि व्यक्ति का अन्य कोई बचत खाता हो, तो उस खाते को जन-धन खाते में रूपांतरित भी कराया जा सकता है। जन-धन खाता खोलने के लिए केवायसी के तहत दस्तावेजों की जाँच की जाती है। योजना के तहत जिस व्यक्ति का कोई अन्य अकाउंट न हो, वह बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) खाता किसी भी बैंक शाखा या बिजननेस करेस्पॉण्डेंट (बैंकमित्र) आउटलेट में जीरो बैलेंस के साथ खुवा सकता है। यदि खाताधारक को चेकबुक की जरूरत हो, तो उसे न्यूनतम् बैलेंस संबंधी शर्तों को पूर्ण करना होता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों के जीवन में पीएम जन-धन योजना के योगदान के विषय में एक बार कहा था कि यह एक ऐसी पहल है, जिसने भारत के विकास के मार्ग को हमेशा के परिवर्तित किया है। इस योजना ने अनेक भारतीयों के लिए वित्तीय समावेशन तथा गौरवपूर्ण जीवन व सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया है।

गुजरात सरकार का बड़ा फैसलाः चार हजार पुराने शिक्षकों की भर्ती की घोषणा

अपडेट किया गयाः 31 अगस्त

गुजरात शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। जिसमें। राज्य शिक्षा विभाग ने 4000 पुराने शिक्षकों की भर्ती निकाली है। जिसमें 2000 माध्यमिक और 20 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 12 सितंबर से 26 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

राज्य शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. जिसमें गैर सरकारी अनुदान के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए लगभग 4000 पुराने शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने माध्यमिक में करीब 2000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है.

राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले महीने 12 सितंबर से 26 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.

वडोदरावासियों ने पीएमओ से की शिकायतः 'गंदे पानी की दुर्गंध से अब हो रही उल्टी': नगरसेवक, अधिकारी नहीं उठाते फोन

वड़ोदरा 31 अगस्त

बाढ़ः वड़ोदरा शहर के अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है, या कम हो गया है। इस बीच, अटलादरा की एक सोसायटी सायरंग हाइट्स के निवासी पिछले पांच दिनों से जलभराव के कारण काफी परेशान हैं। इस क्षेत्र में जलजमाव की समस्या को यहां के निवासियों ने पहले भी मीडिया के माध्यम से उजागर किया था. लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता. पांच दिनों से अधिक समय से बाढ़ का पानी भरा हुआ है और अब इससे दुर्गंध आने लगी है.

तो स्थानीय युवा कुशाग्र पुरोहित ने लिखा कि पांच दिनों से सड़क पर पानी भरा हुआ है. अब इसमें नर्क जैसी गंध आ रही है। ऐसे में लोगों को उल्टियां होने लगी हैं. अटलादरा क्षेत्र में सायरंग हाइट्स और अन्य सोसायटियों की ओर जाने वाली सड़क पर पिछले पांच दिनों से पानी भरा हुआ है. अब इसमें नर्क जैसी गंध आ रही है। ऐसे में लोगों को उल्टियां होने लगी हैं और निकासी नहीं हो रही है. यह पानी अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है.

एक स्थानीय युवा बुद्धिमान पुजारी ने इस मामले में सिस्टम की आंखें खोलने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का सहारा लिया है। उन्होंने लिखा कि हमारे इलाके के 2500 लोग बाढ़ के पानी के कारण अपने घरों में फंसे हुए हैं. हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता. किसी को हमारी समस्या की परवाह नहीं है. स्थानीय नगरसेवक, नगर निगम अधिकारी हमारे किसी भी फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं।

इस ट्वीट में वह लिखते हैं कि पांच दिनों से सड़क पर पानी भरा हुआ है. अब इसमें नर्क जैसी गंध आ रही है। ऐसे में लोगों को उल्टियां होने लगी हैं. वडोदरा निगम हमारी समस्याओं को क्यों नजरअंदाज कर रहा है। हमें मानसिक और शारीरिक बीमारी की स्थिति में धकेलने के लिए धन्यवाद।

कुशाग्र पुरोहित ने जिला कलेक्टर, सांसद डॉ. हेमांग जोशी, राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी और वडोदरा नगर पालिका के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को टैग करके उनकी समस्या को उजागर करने की कोशिश की है। बताया गया है कि इससे पहले क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए कुशाग्र पुरोहित ने सीधे पीएमओ से भी ज्ञापन दिया गया था. हालाँकि, इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सिस्टम द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 7 वें 'राष्ट्रीय पोषण माह 2024' का गांधीनगर से राज्यव्यापी प्रारंभ कराया

गांधीनगर 31 अगस्त, 2024 : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का गांधीनगर से राज्यव्यापी प्रारंभ कराते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रीय पोषण अभियान माता एवं बाल स्वास्थ्य से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को बदलने का नूतन दृष्टिकोण बना है।

श्री पटेल ने इस संदर्भ में कहा कि 'सही पोषण-देश रोशन' के ध्येय के साथ माता व बालक के सुपोषण एवं स्वस्थता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारतें2047' का संकल्प साकार करने में पोषण माह महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

प्रधानमंत्री ने देश में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पोषण की स्थिति पर ध्यान केन्द्रित कर कुपोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान प्रारंभ करवाया था।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रतिवर्ष समग्र सितंबर महीने को पोषण मोह के रूप में मनाने की परंपरा की 7वीं श्रृंखला का शनिवार को गांधीनगर में केन्द्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की प्रेरक उपस्थिति में शुभारंभ कराया।

देश भर में सातवें चरण का यह पोषण माह एनीमिया निवारण, ग्रोथ मॉनिटरिंग, टेक्नोलॉजी के उपयोग से सुशासन तथा पारदर्शिता द्वारा सेवा वितरण, पोषण भी-पढ़ाई भी एवं पूरक आहार की थीम के साथ मनाया जाने वाला है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केन्द्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी तथा राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया ने इस अवसर पर सांकेतिक रूप से बच्चे को अन्नप्राशन की बूंदें पिलाईं, व्हाली दीकरी योजना की लाभार्थी को लाभ वितरण, गर्भवती महिला व स्तनपान कराने वाली माता एवं किशोर आयु की बेटी को पोषक आहार किट तथा स्वावलंबन योजना की लाभार्थी बहन को सहायता चेक का वितरण किया। मुख्यमंत्री के करकमलों से इस अवसर पर राज्य सरकार की नई नारी गौरव नीति 2024 भी लॉन्च की गई।

श्री भूपेंद्र पटेल ने जोड़ा कि राष्ट्रहित के अभियानों में जन भागीदारी को जोड़ कर 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को साकार करने की जो प्रेरणा प्रधानमंत्री ने दी है, उसके फलस्वरूप पोषण माह अब कुपोषण के विरुद्ध संघर्ष का जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने गुजरात में माताओं, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों तथा बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के विषय में राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की गहन भूमिका प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि बच्चों और विशेषकर आदिजाति क्षेत्रों के बच्चों का पोषण स्तर ऊँचा लाने के लिए दूध संजीवनी योजना में सरकार लगभग 13 लाख से अधिक बच्चों को पाश्चुराइज्ड फोर्टीफाइड फ्लेवर्ड मिल्क देती है। इतना ही नहीं; टेक होम राशन, पोषण सुधा व मुख्यमंत्री मातृ शक्ति जैसी योजनाओं द्वारा अतिरिक्त प्रोटीन व पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। उन्होंने जोड़ा कि ऐसी सर्वग्राही पोषण योजनाओं के गुजरात में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं और अब तक 45 लाख लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की माताओं व बच्चों के पोषण के साथ धरती माता के पर्यावरणीय पोषण का ध्यान रखते हुए 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान प्रारंभ करवाया है। मुख्यमंत्री ने गौरवपूर्वक उल्लेख किया कि गुजरात की सभी 53 हजार आँगनबाड़ियों में इस अभियान के अंतर्गत वृक्ष रोपण, वृक्ष पालन, जतन व संरक्षण का आयाम सरकार ने अपनाया है। उन्होंने सभी के सामूहिक पुरुषार्थ से इस सातवें मोषण माह को उपलब्धि की नई ऊँचाइयाँ पार कराने का आह्वान किया। राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ अवसर पर केन्द्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत ने आजादी के अमृतकाल में प्रवेश किया है, तब विकसित भारत की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए देश को कुपोषण मुक्त बनाने में पोषण अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा महिलाओं व बच्चों के विकास व पोषण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के 'मन की बात' के इस बार के संस्करण का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण माह के विषय में कहा था कि देश के बच्चों व महिलाओं को उचित पोषण देना देश की प्राथमिकता है। केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पोषण अभियान अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में 3.17 करोड़ से अधिक समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 का 'राष्ट्रीय पोषण माह' विभिन्न थीम आधारित मनाने का आयोजन किया है; जिसमें एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पूरक आहार, पोषण भी-पढ़ाई भी (पीबीपीबी), सुशासन, पारदर्शिता व सक्षम सेवा पहुँचाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग शामिल हैं। सर्वग्राही पोषण से जुड़ी सभी आवश्यकताओं को समाहित करने वाली सभी थीमों पर आधारित विभिन्न गतिविधियाँ इस पोषण माह के दौरान समग्र देश में आयोजित की जाएंगी।

'बीजेपी हाय...हाय...गृहमंत्री-मुख्यमंत्री शर्म करो', वडोदरा में कांग्रेस-पुलिस में झड़प

वडोदरा ,31 अगस्त

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वडोदरा में विरोध प्रदर्शन: वडोदरा में बाढ़ की भयावह स्थिति के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी. आज वडोदरा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और 'भाजपा हाय...हाय...', 'शहर विधायक, सांसद, गृह मंत्री-मुख्यमंत्री शर्म करो...शर्म करो...' के नारे लगाए। प्रदर्शन की योजना के बाद पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की. हालाँकि, मामला तब बढ़ गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिना कोई शांत रवैया दिखाए आक्रामक नारे लगाना जारी रखा और पुलिस के साथ हाथापाई शुरू हो गई।

कांग्रेस ने आक्रामक प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय पर कब्ज़ा कर लिया. इस बीच कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई. पुलिस ने शर्त रखी थी कि कलेक्टर को आवेदन पत्र देने सिर्फ पांच लोग ही जायेंगे. लेकिन सभी कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय में घुस गये. इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई.

कांग्रेस ने याचिका दाखिल कर बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की थी. विरोध कर रहे उग्र होते देख संयुक्त पुलिस आयुक्त को भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचना पड़ा।

कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने कहा, 'हर बार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री शहर में आते हैं. फिर पुलिस या तो हमें पकड़ लेती है या गिरफ़्तार कर लेती है. कैशडॉल के नाम पर 1000-2000 रुपये देकर वडोदरा की जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है. लोगों का हाउस टैक्स, लाइट बिल एक साल के लिए माफ किया जाए। विश्वामित्री के तट पर दबाव बनाकर बनाये गये मॉल और होटल तथा भाजपा नेताओं के बंगले तोड़े जाने चाहिए। सरकार के मंत्री केवल फोटो सेशन के लिए वडोदरा आ रहे हैं।'

गुजरात कांग्रेस प्रमुख आज जामनगर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगो से मिलेंगे

अहमदाबाद (ईएमएस) राज्य में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई हैं हालांकि अब राज्य में बारिश थमने से लोगों के जलभराव से राहत मिलने लगी हैं गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल कल 1 सितंबर 2024, रविवार को जामनगर में विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी शिकायतें सुनेंगे। शक्तिसिंह गोहिल ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं-नेताओं से राज्य में भारी बारिश से प्रभावित नागरिकों की स्थानीय स्तर पर मदद करने की अपील की है। बता दें कि गुजरात में पिछले 6 दिनों की बारिश और बाढ़ से बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ हैं मेघ तांडव के बीच 6 दिनों में राज्य में 47 लोगों की मौत हो गई और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की खाद्य सामग्री से लेकर घरेलू सामान बर्बाद हो चुका हैं दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने सबसे अधिक प्रभावित जामनगर, देवभूमि द्वारका और वडोदरा का दौरा किया था

वलसाड जिला कलेक्टर नैमेश दवे की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक, हाईवे पर गड्ढों के मुद्दे पर कलेक्टर ने लिया सख्त कदम

वलसाड, 31अगस्त

वलसाड जिला कलेक्टर श्री नैमेश दवे एवं जिला विकास अधिकारी श्री अतिराग चपलोत की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में जनता के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं जिला कलेक्टर ने भी गड्ढों एवं जानलेवा दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों, जिला पंचायत और राज्य पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर तीनों विभागों के अधिकारियों को जिले में किसी भी गड्ढे वाली सड़क को युद्धस्तर पर दुरुस्त करने को कहा गया. उन्होंने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हाइवे पर गड्ढे के कारण कोई दुर्घटना हुई और जानमाल की क्षति हुई तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी को भी एफआईआर में आरोपी बनाया जायेगा और सख्ती से कहा जायेगा कि सभी काम पूरे करायें. सड़कें.

समन्वय बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनहर भाई पटेल ने कहा नहीं. 48 पर जानलेवा गड्ढे के मुद्दे पर एनएचएआई के अधिकारियों को सख्त लहजे में बताया गया कि पारडी वल्लभ आश्रम के पास हाईवे पर गड्ढे के कारण दुर्घटना में संजय मित्थलभाई पटेल (श्री 52, निवासी कुंभारिया, पारडी) की मौत हो गई, जिसके बाद हाईवे अथॉरिटी रात दो बजे गड्ढे की मरम्मत की तो यह कार्रवाई पहले ही क्यों नहीं की गयी? उन्होंने अधिकारियों के कामकाज का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब तक लोगों के लिए सुरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बन जाते, तब तक टोल टैक्स वसूलना बंद करें. इसी मामले में वलसाड डांग सांसद और लोकसभा दंडक धवलभाई पटेल ने भी हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि उन्हें 48 घंटे के भीतर हाईवे पर गड्ढे भरने को कहा गया था लेकिन काम अभी भी अधूरा है. बलीठा हाईवे पर पानी भरा रहता है और जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, कई स्थानों पर सर्विस रोड भी नहीं बनने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस संबंध में हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि हम गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं, जिसमें कलेक्टर ने कहा कि हर दिन किए गए काम की फोटो के साथ रिपोर्ट पेश करें. जिला पंचायत प्रमुखश्री से पूछा गया कि वलसाड तालुका के काकड़मती गांव में पावरग्रिड कॉर्पोरेशन की बिजली लाइन के कारण पेड़ों और फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा किसान को नहीं दिया गया है, तो पावरग्रिड के उप प्रबंधक ने कहा कि यह एक बैंक है मुद्दा।

सांसद श्री धवल पटेल ने वलसाड, पारडी और धरमपुर प्रांतों के प्रत्येक प्रांतीय कार्यालय में जिले में एससी/एसटी/ओबीसी के जाति पैटर्न के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित करने को कहा। लोक सेवा केंद्र से दो से तीन दिन के अंदर जाति का सैंपल दे दिया जाता है। कोई मिसाल नहीं बची. इसके अलावा अनुदान प्रशासक ने बताया कि 34167 में से 31018 दावों का निस्तारण कर दिया गया है. अब 3149 दावे लंबित हैं जिनमें गिर फाउंडेशन कार्यालय से 2005 से पहले के कब्जे के आंकड़ों का सत्यापन कर निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। सांसद ने वलसाड रेलवे स्टेशन पर होने वाली 13 अलग-अलग समस्याओं को लेकर सवाल उठाए, लेकिन बैठक में एरिया मैनेजर या सक्षम अधिकारी के मौजूद नहीं होने पर कलेक्टर ने एआरएम की ओर से आए क्लर्क को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या अधिकारी मौजूद हैं? समन्वय बैठक में समस्याओं का समाधान हो सके इसके लिए अपने अधिकारी को समन्वय बैठक में उपस्थित रहने को कहा ताकि लोगों के सवालों का जवाब दिया जा सके. इसके साथ ही कलेक्टर ने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि समन्वय बैठक में किसी भी प्रतिनिधि को न भेजा जाये, कोई भी अधिकारी बिना किसी अनिवार्य कारण के अनुपस्थित नहीं रह सकेगा। सांसद ने कपराडा के बारपुडा में श्मशान घाट में शेड की व्यवस्था करने को कहा और आगे कहा कि धरमपुर और कपराडा तालुका के कई गांवों में श्मशान घाट नहीं हैं और लोगों को मानसून के दौरान परेशानी उठानी पड़ती है, इसलिए एक सर्वेक्षण कराने को कहा गया. इसके अलावा सांसद ने डूंगरी में पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सा अधिकारी का पद दोबारा खोलने, कृषि उपज मंडी समिति धरमपुर की भूमि आवंटन, सरदार मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन का किराया बढ़ाने, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड के लिए अधिग्रहीत भूमि वापस करने के मुद्दे पर चर्चा की. रेल परियोजना और वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे भुगतान, धरमपुर पुस्तकालय में पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान, मछुआरों को होने वाली कठिनाइयाँ, उमरगाम में मछली लैंडिंग केंद्र का संचालन, तीथल समुद्र तट पर बैंकों, लाइट, हाई मास्ट टॉवर और टूटी टाइल्स आदि का काम। , दांडी में नहर की मरम्मत, दो हाई मास्ट टावर और 3 किमी सुरक्षा दीवार, नारगोल सुरक्षा दीवार और जिले के गांवों में मोबाइल नेटवर्क की कमी सहित कुल 17 प्रश्न प्रस्तुत किए गए।

आईपीडब्ल्यूई गांधीनगर 2024 के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ

गांधीनगर के महात्मा मंदिर स्थित कन्वेंशनल सेंटर में इंस्टीटयूशंस आफ परमानेंट वे इंजीनियर्स आईपीडब्ल्यूई - गांधीनगर 2024 के दो दिवसीय सेमिनार की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईपीडब्ल्यूई के संरक्षक एवं रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर श्री अनिल कुमार खंडेलवाल थे।

इस अवसर पर कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री अमित गुप्ता ने अपने स्वागत उद्बोधन में बताया कि यह आईपीडब्ल्यूई का 30वां सेमिनार है जो गांधीनगर गुजरात में आयोजित की जा रही है, यह पश्चिम रेलवे का सौभाग्य है कि हमें इस गौरवपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने का अवसर मिल रहा है।

यह सेमिनार सिविल इंजिनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर आईडिया एक्सचेंज करने एवं अपने नॉलेज व अनुभवों को साझा करने का एक महत्वपूर्ण फोरम है। रेल पथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई तकनीक एवं आधुनिकरण के युग में , जिसमें ब्रिज इंजीनियरिंग रेल पथ इंजीनियरिंग सहित प्रोजेक्ट प्लानिंग में उनको मूर्त रूप देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सेमिनार में रेलवे इंजीनियर्स द्वारा उनके क्षेत्र की उन सभी संबंधित समस्याओं एवं चैलेंज जिनका सामना वे कर रहे हैं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है ।

माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए अपने शुभकामना सन्देश में उन्होंने इस सेमिनार की सफलता की कामना करते हुए बताया कि भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर्स मे से है और जब भी देश में जटिलतम प्रोजेक्ट को करना होता है तो रेलवे की बात आती है। रेलवेगरीब व मध्यम वर्ग के साथ साथ जन जन की सवारी है। ऐसे में हम कैसे नई टेक्नोलॉजी व नई फैसिलिटी लाए औरइसमेंट्रैकसे संबंधित जो इनोवेशन करने हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में रेलवे बोर्ड के मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर श्री अनिल कुमार खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय रेलवे तेजी से विकास की ओर अग्रसर है जिसमें आधुनिक ट्रैक स्ट्रक्चर, आरओबी व आरयूबी का तेजी से निर्माण करना और नई रेलवे कॉरिडोर की प्लानिंग में उनको मूर्त रूप देना हमारी प्राथमिकता है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। जहां दो करोड़ यात्री व 5 मिलियन टर्न कार्गो प्रतिदिन परिवहन किया जाता है एवं 8000 रेलवे स्टेशनों को जोड़ती 20000 ट्रेने प्रतिदिन चलाई जाती है। यह न केवल देश की जीवन रेखा है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने में भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, जिसमें नेटवर्क का विस्तार करना तथा 2030 तक 3000 मिलियन टन माल परिवहन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सेफ्टी हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए एवं हमें सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के स्लोगन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

कार्यक्रम के प्रारंभ में माननीय अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इस वर्ष की सेमिनार के लिए जो विषय चयनित किए गए हैं, उनमें आरओबी व आरयूबी का तेजी से निर्माण करना ताकि लेवल क्रासिंग को हटाया जा सके। फास्ट ट्रेक डिलीवरी आफ प्रोजेक्ट विषय पर सफल केस स्टडी पर विचार विमर्श करना जैसे महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित है। साथ ही एलिवेटेड कॉरिडोर (एलिवेटेड स्टेशन सहित) की परियोजनाओं को साकार करना जिसमें 250 क्स्ज की गति की संभावना हो। यह सभी बिंदु वर्तमान में समकालीन एवं महत्वपूर्ण है जिस पर तकनीकी चर्चा इस सेमिनार के दौरान की जाएगी। यह सेमिनार दैनिक कार्य के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं व पहलुओं व उन पर भी बेहतर रणनीति बनाने में व उनके क्रियान्वयन में मदद करेगी।

इस सेमिनार में आईपीडब्ल्यूई के अध्यक्ष व रेलवे बोर्ड में एडिशनल मेंबर सिविल इंजीनियरिंग, श्री बृजेश गुप्ता, इरीसेन पुणे के डायरेक्टर जनरल श्री एस के झा, उपाध्यक्ष व रेलवे बोर्ड के प्रमुख एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रिज श्री रविंद्र गोयल, जनरल सेक्रेटरी व प्रमुख मुख्य इंजीनियर उत्तर रेलवे श्री बीपी सिंह सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी गण डीआरएम अहमदाबाद डिवीज़न श्री सुधीर कुमार शर्मा तथा देश भर से विभिन्न रेलों के वरिष्ठ रेलवे इंजीनियर्स ने भाग लिया।

अंकलेश्वर-पनोवी के बीच 5 किलोमीटर लंबा जाम, वाहनों की लगी लंबी कतारें

वडोदरा,31 अगस्त

बारिश के ब्रेक के दौरान अंकलेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वडोदरा से सूरत ट्रैक पर पांच किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लग गया। अंकलेश्वर-पानोली के बीच संकरा अमलखाड़ी पुल निर्माणाधीन है। काफी समय से पुल की मरम्मत का काम काफी धीमी गति से चल रहा है. अंकलेश्वर के राजपीपला चौक के पास जीआईडीसी की ओर जाने वाली सड़क का काम जोरों पर चलने के कारण वालिया चौक और नीलेश चौक के पास ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है. अंकलेश्वर नेशनल हाईवे पर वडोदरा से सूरत तक ट्रैक पर आज सुबह से जाम की स्थिति बन गई. हाईवे पर 5 से 6 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं.

पिछले सप्ताह हुई लगातार बारिश के कारण भरूच-अंकलेश्वर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे राजमार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। हाईवे अथॉरिटी के साथ-साथ आई.आर.बी. आए दिन लगने वाली जाम की समस्या पर एजेंसी के अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं।

वर्तमान में, राजपीपला चौक के पास अंकलेश्वर जीआईडीसी के लिए एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इससे हाईवे पर वालिया चौक समेत नीलेश चौक के पास वाहनों का आवागमन बढ़ गया है। जिससे हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा है और हाईवे पर जाम की स्थिति बन रही है. हालांकि बार-बार जाम की समस्या से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बारिश के ब्रेक के दौरान अंकलेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वडोदरा से सूरत ट्रैक पर पांच किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लग गया। अंकलेश्वर के राजपीपला चौक के पास जीआईडीसी की ओर जाने वाली सड़क का काम जोरों पर चलने के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई

भारतीय रेलवे इंजीनियर्स दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरः रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

- आईपीडब्ल्यूई गांधीनगर 2024 के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ

गांधीनगर (ईएमएस) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे इंजीनियर्स दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर हैं यह इससे पता चलता है कि जब भी जटिलतम प्रोजेक्ट करना होता है तब रेलवे की बात आती हैं अश्विनी वैष्णव गुजरात के गांधीनगर में आयोजित आईपीडब्ल्यूई के दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उदघाटन के अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थें दरअसल गुजरात की राजधानी गांधीनगर के महात्मा मंदिर स्थित कन्वेंशनल सेंटर में इंस्टीटयूशंस आफ परमानेंट वे इंजीनियर्स आईपीडब्ल्यूई -गांधीनगर 2024 के दो दिवसीय सेमिनार की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईपीडब्ल्यूई के संरक्षक एवं रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कुमार खंडेलवाल थे। इस अवसर पर कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य इंजीनियर अमित गुप्ता ने बताया कि यह आईपीडब्ल्यूई का 30वां सेमिनार है जो गांधीनगर गुजरात में आयोजित की जा रही है, यह पश्चिम रेलवे का सौभाग्य है कि हमें इस गौरवपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने का अवसर मिल रहा है। यह सेमिनार सिविल इंजिनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर आईडिया एक्सचेंज करने एवं अपने नॉलेज व अनुभवों को साझा करने का एक महत्वपूर्ण फोरम है। रेल पथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई तकनीक एवं आधुनिकरण के युग में , जिसमें ब्रिज इंजीनियरिंग रेल पथ इंजीनियरिंग सहित प्रोजेक्ट प्लानिंग में उनको मूर्त रूप देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सेमिनार में रेलवे इंजीनियर्स द्वारा उनके क्षेत्र की उन सभी संबंधित समस्याओं एवं चैलेंज जिनका सामना वे कर रहे हैं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है।

इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए अपने शुभकामना सन्देश में उन्होंने इस सेमिनार की सफलता की कामना करते हुए बताया कि भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर्स में से है और जब भी देश में जटिलतम प्रोजेक्ट को करना होता है तो रेलवे की बात आती है। रेलवे गरीब व मध्यम वर्ग के साथ साथ जन जन की सवारी है। ऐसे में हम कैसे नई टेक्नोलॉजी व नई फैसिलिटी लाए और इसमें ट्रैक से संबंधित जो इनोवेशन करने हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में रेलवे बोर्ड के मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कुमार खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय रेलवे तेजी से विकास की ओर अग्रसर है जिसमें आधुनिक ट्रैक स्ट्रक्चर, आरओबी व आरयूबी का तेजी से निर्माण करना और नई रेलवे कॉरिडोर की प्लानिंग में उनको मूर्त रूप देना हमारी प्राथमिकता है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। उन्होंने कहा कि सेफ्टी हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए एवं हमें सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के स्लोगन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

इस सेमिनार में आईपीडब्ल्यूई के अध्यक्ष व रेलवे बोर्ड में एडिशनल मेंबर सिविल इंजीनियरिंग, बृजेश गुप्ता, इरीसेन पुणे के डायरेक्टर जनरल एस के झा, उपाध्यक्ष व रेलवे बोर्ड के प्रमुख एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रिज रविंद्र गोयल, जनरल सेक्रेटरी व प्रमुख मुख्य इंजीनियर उत्तर रेलवे बीपी सिंह सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी गण डीआरएम अहमदाबाद डिवीज़न सुधीर कुमार शर्मा तथा देश भर से विभिन्न रेलों के वरिष्ठ रेलवे इंजीनियर्स ने भाग लिया।

सन मोबिलिटी ने वीरा वाहन के साथ भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए भारत की पहली मॉडयुलर स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पेश की

बैंगलुरू,29 अगस्त

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के अग्रणी प्रदाता, सन मोबिलिटी ने आज हैवी इलेक्ट्रिक वाहनों (एचईवी) के लिए दुनिया की पहली बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पेश की। कंपनी ने बैंगलोर स्थित अग्रणी बस निर्माता, वीरा वाहन के साथ साझेदारी में इंटरसिटी और ग्रामीण मार्गों के लिए भारत की पहली 10.5 मीटर बैटरी स्वैपेबल बसें लॉन्च की हैं। यह लॉन्च बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीओसीआई) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, प्रवास 4.0 में किया गया। वीरा वाहन के सभी वाहनों में इसी तकनीक का उपयोग होगा।

उत्सर्जन में कमी लाने, हवा की गुणवत्ता सुधारने, और परिवहन सेक्टर की एफिशियंसी बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक वाहनों की फ्लीट, खासकर हैवी वाहनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाना आवश्यक है। सन मोबिलिटी का प्रमाणित और परखा गया स्मार्ट बैटरी समाधान हल्के, मध्यम और भारी ट्रकों एवं बसों के लिए उपयुक्त है, जिनमें 3 टन से 55 टन तक के सकल वजन वाले वाहन (जीडब्लूवी) आते हैं।

अशोक अग्रवाल, सीईओ-एचईवी, सन मोबिलिटी ने कहा, ''बैटरी स्वैपिंग से बसों की अग्रिम लागत में 40 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे इसकी अग्रिम लागत पारंपरिक डीज़ल से चलने वाली बसों से मेल खाने लगेगी और फाईनेंस की आसान उपलब्धता से फ्लीट मालिकों को इलेक्ट्रिक बसें अपनाना आसान हो जाएगा। साथ ही, इससे फ्लीट मालिकों के लिए संचालन की लागत में 20 प्रतिशत तक की कमी आएगी, साथ ही बैटरी स्वैपिंग की प्रक्रिया केवल 3 मिनट में पूरी हो जाने से बसों का ज्यादा अपटाईम और ज्यादा उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। बैटरी के कॉम्पैक्ट और लाईट फॉर्म फैक्टर द्वारा ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता प्राप्त होगी।

अशोक अग्रवालने कहा, ''सन मोबिलिटी ने बस ऑपरेटर्स के लिए स्वामित्व की ऊँची लागत, भारी वाणिज्यिक वाहनों की फाईनेंसिंग अपर्याप्त होना, लंबी चार्जिंग अवधि के कारण लंबा डाउनटाईम, और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के भारी दबाव जैसी मुख्य बाधाओं को दूर करके भारी वाणिज्यिक वाहनों में नई जान फूंक दी है। वीरा वाहन के साथ हमारी साझेदारी एक महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि हम भारत की पहली मॉडयुलर स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पेश कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स को एक व्यवहारिक और किफायती समाधान प्रदान करेगी, जिससे उनकी एफिशियंसी बढ़ेगी और संचालन की लागत में कमी आएगी।''

नारोल में एक ट्रांसपोर्ट पार्सल द्वारा ऑर्डर की गई बीयर की मात्रा जब्त की गई

अहमदाबाद,31 अगस्त

पीसीबी स्टाफ ने शहर के नारोल में एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में मुंबई से आए पार्सल से बड़ी मात्रा में बीयर जब्त की। एक अन्य घटना में चांदखेड़ा पुलिस ने जंदल सर्कल से 20 किलोमीटर तक एक संदिग्ध कार का पीछा किया, जिसमें कार के साथ शराब की बोतलें मिलीं ड्राइवर कोटेश्वर. पीसीबी के पीआईएमसी चौधरी के कर्मचारियों को नारोल में पिपलाज-पिराना रोड पर स्थित सौराष्ट्र रोडवेज ट्रांसपोर्ट के गोदाम में मुंबई से आए एक पार्सल में शराब होने की सूचना मिली। इसके आधार पर पुलिस ने मुंबई मुलुंड कॉरपोरेट पार्क से एक पार्सल और भिवंडी से अहमदाबाद पहुंचाए गए एक पार्सल पर छापा मारा और निरीक्षण किया। इसमें भारी मात्रा में पैक्ड बीयर के टिन मिले।

शुरुआती जांच में पता चला कि पार्सल भोपाल के मारुतिनंदन कॉम्प्लेक्स स्थित धरम इंटरप्राइजेज नाम के ऑफिस में जा रहा था. जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. एक अन्य घटना में चांदखेड़ा थाने के स्टाफ को सूचना मिली कि एक व्यक्ति राजस्थान से कार में शराब लेकर जुडाल सर्कल के पास से गुजरने वाला है. इसलिए पुलिस ने निगरानी स्थापित की और संदिग्ध कार को रोकने का संकेत दिया। लेकिन, ड्राइवर ने कार रोकने की बजाय चांदखेड़ा की ओर भगा दी। बाद में वह कार को कोटेश्वर के पास छोड़कर भाग गया। पुलिस को कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली. चांदखेड़ा पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है.

मालिक, मुद्रक-प्रकाशक व सम्पादक : लक्ष्मीचन्द जी. अग्रवाल द्वारा ब्रिजाशा ऑफसेट, सरसपुर, अहमदाबाद में मुद्रित करवाकर, स्वेतप्रित बिल्डिंग, खासवाड़ी, बहुचराजी रोड़, वड़ोदरा से प्रकाशित किया। प्रात:कालीन E-mail: janhitaishi@yahoo.co.in Mob.9375504122 R.N.I. 64278/96